सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 235, नई दिल्ली । सोमवार, 28 अक्टूबर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया...

03 दिल्ली में फिर खुलेंगी शराब की प्रीमियम दुकानें; मिलेंगे सभी प्रमुख ब्रांड

06 जैविक खाद्य विकल्पों के लाभ और वास्तविकता

08 क्या नेता वोटरों को नारों में उलझा पाएंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) भारत सरकार द्वारा सेक्शन 194जी पर मसौदा अधिसूचना जारी, जानें

संजय बाटला

स्कूल वाहन एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत वाहन चालकों के लिए मोटर वाहन नियम में बदलाव के लिए मसौदा अधिसूचना, जाने क्या किया जा रहा है बदलाव आपकी जानकारी हेतु बता दें 8 नवंबर तक उच्चतम न्यायालय द्वारा हल्के मोटर वाहन के लाइसेंस पर बड़ा फैसला आ जाएगा और उसके साथ ही सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन नियम में 67 बदलाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी जिसके अनुसार हल्के मोटर वाहन को दो श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इन्ही 67 बदलावों में 62वे नंबर है शैक्षिक संस्थानों के वाहन चालकों के बदलाव का प्रस्ताव

सर्वप्रथम जाने मसौदा अधिसूचना

194जी. स्कूल बस, स्कूल वैन या शैक्षणिक संस्थान बस से संबंधित अपराधों के लिए दंड-

जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों या कर्मचारियों का परिवहन करते समय किसी स्कूल बस या स्कूल वैन या शैक्षणिक संस्था की बस या ऐसे अन्य वाहन को, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, चलाएगा, चलाने देगा या चलाने देगा, वह इस अधिनियम के अधीन उस अपराध के लिए तत्संबंधी शास्ति या जुर्माने की दुगुनी राशि से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्कूल बस से तात्पर्य ऐसे वाहन से है जिसमें तेरह या इससे अधिक यात्री बैठ सकते हैं, तथा चालक को छोड़कर, वह वाहन विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बालकों के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है।

स्पष्टीकरण 2: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्कूल वैन का तात्पर्य एआईएस: 204 के तहत परिभाषित वाहन से है।

इस मसौदा अधिसूचना के जारी होने से यह स्पष्ट नजर आ रहा है की भारत सरकार द्वारा भारत देश में व्यवसायिक वाहनों को चलाने वाले चालकों को अलग अलग श्रेणी में

करके (पूर्व में ट्रक चालकों द्वारा विरोध के प्रति की घोषित हड़ताल पर जिस क़ानून को रोका था) **मोटर वाहन नियम में बदलाव कर लागू करने की अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया है।**

भारत देश में सभी चालकों के प्रति कार्य करने वाली यूनियनस, एसोसिएशन एवम् प्रतिनिधि इस बदलाव के ख़िलाफ़ एकजुट आवाज़ उठा सकते हैं और जरूरत महसूस होगी तो फिर से राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल हो सकती हैं और शिक्षण संस्थानों के साथ ही अन्य व्यवसायिक श्रेणी के वाहन चालक चक्का जाम कर सकते हैं।

सड़क परिवहन एवम्राजमार्ग मंत्रालय को इस मसौदा अधिसूचना पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है अन्यथा पूरे देश में वाहनों के चक्केजाम हो सकते हैं।

केरल सरकार के प्रोजेक्ट को लेकर बोले रेल मंत्री, 'ये मुद्दे सुलझ जाएं तो लागू हो सकती है के-रेल'

केरल सरकार की रूकी हुई के-रेल परियोजना को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगर कुछ मुद्दों को सुलझा लिया जाए तो ये योजना लागू हो सकती है। के-रेल प्रोजेक्ट का उद्देश्य केरल के पूरे उत्तर और दक्षिण खंड में परिवहन को आसान बनाना और यात्रा के समय को वर्तमान में 12 से 14 घंटे के मुकाबले चार घंटे से भी कम करना है।

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तकनीकी और पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझा लिया जाए तो केरल सरकार की रुकी हुई के-रेल परियोजना आगे बढ़ सकती है। राज्य सरकार की सेमी-हाई-स्पीड रेल परियोजना विपक्ष के विरोध का सामना कर रही है और केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है। के-रेल का उद्देश्य केरल में यात्रा के समय को काफी कम करना है।

कुछ समय के लिए स्थगित की गई थी परियोजना

केरल सरकार की महत्वाकांक्षी के-रेल सेमी-हाई-स्पीड रेल परियोजना फिर से चर्चा में है क्योंकि केंद्र ने रविवार को आश्वासन दिया कि अगर राज्य के अधिकारी इसके डिजाइन में तकनीकी और पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझा लेते हैं तो परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। विपक्षी दलों और आम जनता के तीव्र विरोध और केंद्र सरकार से अनुमति न मिलने के कारण कई करोड़ रुपये की यह परियोजना कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी।

केरल सरकार की परियोजना को मिली नई उम्मीद

राज्य सरकार की परियोजना को नई उम्मीद देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उन्होंने पिछली बार नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से इस मामले पर चर्चा की थी। 'मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि के-रेल के डिजाइन में जो भी तकनीकी और पर्यावरणीय मुद्दे हैं, कृपया उनका शीघ्र समाधान करें, ताकि इस परियोजना को भी आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी ओर से - एनडीए सरकार - हम सहकारी संघवाद में विश्वास करते हैं।

ग्रैप-2 लागू होने के बाद भी क्यों बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण? खूब हो रहा नियमों का उल्लंघन, कार्रवाई तेज

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। पीयूसी के बिना वाहन चल रहे हैं पुराने वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। सीएक्यूएम ने सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि ग्रेप 2 के प्रावधानों को लागू किया जा सके।

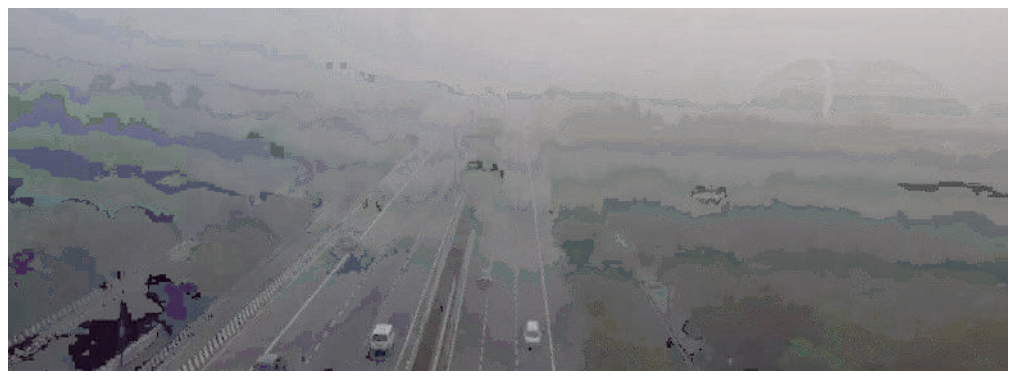

नई दिल्ली। एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगे ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान)- एक व ग्रेप-2 के प्रावधानों और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। एनसीआर की सड़कों पर बगैर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के वाहन रफ्तार भर रहे हैं। अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहन भी सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे हैं। कई निर्माणाधीन और विध्वंस स्थलों पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेप के नियमों का पालन नहीं करने पर की कार्रवाई के आंकड़े हकीकत दिखा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सीएक्यूएम ने दिल्ली सहित एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सख्ती बढ़ाने और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं।

22 अक्टूबर को ग्रेप-2 के प्रावधानों को लागू किया गया

एनसीआर में 15 अक्टूबर को ग्रेप-एक व 22 अक्टूबर को ग्रेप-2 के प्रावधानों को लागू किया गया था। सीएक्यूएम ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए गए प्रावधानों पर कार्रवाई की निगरानी व फॉलोअप के लिए एनसीआर से संबंधित राज्यों में ग्रेप निगरानी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, जिसका प्रमुख सीएक्यूएम के सदस्य को बनाया गया है। सेंट्रल कंट्रोल रूम व राज्यों के नोडल अधिकारियों के बीच बिना रोकटोक के एक दूसरे तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए एक वाट्सऐप ग्रुप भी बनाया गया है।

विध्वंस स्थलों पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय नहीं

आयोग के अनुसार ग्रेप लगने के बाद 15 से 31 अक्टूबर के बीच एनसीआर में सात हजार निर्माण व विध्वंस स्थलों का निरीक्षण किया गया। जिसमें से 653 निर्माण व विध्वंस स्थलों पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय नहीं किए गए थे। इस वजह से 597 निर्माण व विध्वंस स्थलों पर काम करने वाली एजेंसियों के खिलाफ जुर्माने के रूप में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया गया है। 56 निर्माण व विध्वंस स्थल बंद करा दिए गए हैं।

दिल्ली में कूड़ा जलाने की धटनाएं भी हो रही

एनसीआर में पीयूसी नहीं होने पर 54 हजार वाहनों के चालान किए गए हैं। वहीं समय पूरा होने के बाद भी सड़कों पर रफ्तार भरने वाले 3900 पुराने वाहन जब्त किए गए हैं। करीब 1400 औद्योगिक ईकाइयों व 1300 डीजल जनरेटर (डीजी सेट) का निरीक्षण किया गया। नियमों का पालन नहीं होने पर कई डीजी सेट बंद कराए गए। ठोस कचरा प्रबंधन में भी लापरवाही बरती जा रही है और कूड़ा जलाने की धटनाएं भी हो रही हैं। सीएक्यूएम की टीम ने अवैध मलबा डालने की साइटों का भी निरीक्षण किया है। सीएक्यूएम के अनुसार एनसीआर में ऐसे 5300 निरीक्षण किए गए हैं। इस दौरान कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

वाटर स्प्रिंकलर व एंटी स्माग गन बढ़ाए गए

सीएक्यूएम ने दावा किया है कि सड़कों पर धूल की रोकथाम व पानी की छिड़काव के लिए एनसीआर में वाटर स्प्रिंकलर व एंटी स्माग गन बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में सड़कों की सफाई व धूल हटाने के लिए औसतन 81 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (एमआरएसएम) प्रतिदिन लगाए जाते हैं। वहीं एनसीआर में स्थित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में 36 मशीनें हैं। इसी तरह एनसीआर में प्रतिदिन औसतन 600 वाटर स्प्रिंकलर व 600 एंटी स्माग गन तैनात किए गए हैं।

दिल्ली मैं AQI लेवल पहुंचा 500 के पार

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को AQI 200 आने तक बंद किए जाने की मांग

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली नगर निगम के शिक्षक संगठन शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खत्री ने ट्वीट करके दिल्ली की मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री के साथ साथ DCPCR और NCPCR से गुहार लगाई है कि दिल्ली मैं प्रदूषण का स्तर 500 के पार हो गया है इस आपात स्थित में दिल्ली के स्कूलों को तुरंत बंद कर देने के आदेश जारी किए जाने चाहिए जिससे छात्रों को इस बढ़ते प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके दिल्ली सरकार और निगम के स्कूलों और एडिड स्कूलों और NDMC के स्कूलों के छात्रों की संख्या लाखों में है और उन्हें पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या एक लाख से ऊपर है जब सभी शिक्षक स्कूल आने के लिए अपने निजी साधन का प्रयोग करते हैं तब दिल्ली की सड़कों पर सुबह दोपहर शाम एक लाख से ज्यादा वाहन निकलता है जिसे स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की छुट्टी करके घर से ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू करके रोका जा सकता है।

कुलदीप सिंह खत्री ने बताया कि अगर स्कूलों की तत्काल छुट्टी के आदेश नहीं दिए गए तो बच्चों की सेहत से होने वाले खिलवाड़ के लिए दिल्ली सरकार और निगम प्रशासन दोनों दोषी होंगे बच्चों में खांसी, उल्टी सांस लेने में दिक्कत की शिकायत बनी हुई है ऐसे में दिल्ली सरकार को तुरंत निर्णय लेते हुए दिल्ली के स्कूलों को स्थिति सामान्य होने तक बंद किए जाने के आदेश जारी करने चाहिए।

कुलदीप सिंह खत्री
अध्यक्ष
शिक्षक न्याय मंच नगर निगम

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

हाथ जोड़कर आपसे विनती है.., दिल्ली में डीटीसी बस मार्शल्स की बहाली को लेकर गर्म हुई राजनीति, बीजेपी ने सीएम पर बोला हमला

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली में मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार सुबह 11 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आवास पर जाएंगे. बीजेपी नेता सीएम से बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली का आदेश देने की मांग करेंगे.

वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री आतिश मारलेना हमने आपसे केवल एक ही मांग रखी है की माननीय उपराज्यपाल के आदेश के बाद मार्शल्स और सभी सिविल डिफेंस वालंटियर्स की बहाली का आदेश आपको देना है. 1 तारीख से सभी को काम पर लगना था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है.

हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि उन्हें काम पर वापस लगा लीजिए और इसके लिए कल मैं आपके निवास आ रहा हूं. अपने साथियों के साथ ताकि आप सभी की बहाली का आदेश दे.

उपराज्यपाल ने भी साधा था निशाना

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना

ने शनिवार को मुख्यमंत्री आतिशी से पिछले साल 'बस मार्शल' के पद से हटाए गए 10 हजार नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों (सीडीवी) की पुनः नियुक्ति में तेजी लाने को कहा. आतिशी को लिखे पत्र में सक्सेना ने कहा कि सीडीवी को तत्काल पुनर्नियुक्त करने के उनके स्पष्ट आदेश के बावजूद, उन्हें इस संबंध में मुख्यमंत्री से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन बसों में सीवीडी के तौर पर काम करने वाले करीब 10 हजार व्यक्तियों को राजस्व विभाग और वित्त विभाग की आपत्तियों के बाद पिछले साल नवंबर में हटा दिया गया था.

सक्सेना ने पत्र में कहा, "बेशक आप और आपकी पार्टी के नेता इनकी बहाली का श्रेय लेने की राजनीति करते रहें लेकिन इन आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों के कल्याण में अब और देरी किसी भी तरह से ठीक नहीं है।"

'एलजी को भेजेंगे बस मार्शलों को पक्का करने का प्रस्ताव, सीएम आतिशी का BJP नेताओं को नया चैलेंज

बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चैलेंज करती हूं हम एक हफ्ते में बस मार्शलों को पक्का करने का प्रस्ताव एलजी को भेजेंगे। भाजपा भी एक हफ्ते में उस प्रस्ताव को पास करवा कर दिखाये। बीजेपी को बस मार्शलों के साथ अपनी गंदी राजनीति करना बंद करना चाहिए।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बस मार्शलों की नियुक्ति पर गंदी राजनीति का आरोप लगाते भाजपा और एलजी पर हमला बोला है। आतिशी ने कहा, ₹आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बस मार्शल के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी ही है जो इन्हें नौकरी से निकाले जाने के फैसले का विरोध कर रही है।₹ सीएम आतिशी ने यह बातें रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कही।

भाजपा के इशारे पर निकाले गए बस मार्शल- आतिशी

दिल्ली सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर अक्टूबर 2023 में इन 10 हजार बस मार्शल को नौकरी निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता, विधायक और मंत्री बस मार्शल के साथ उनके आंदोलन में रहे हैं और मांग करते रहे हैं कि उन्हें नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय संविदा कर्मियों को पक्का करने का लालच देती है, मगर पक्का नहीं करती है।

"हमने MCD में 10 हजार सफाई कर्मियों को पक्का किया"

उन्होंने कहा, "राजस्थान में 1 लाख 10 हजार, मध्य प्रदेश में एक लाख 80 हजार संविदा कर्मी हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इनकी बड़ी संख्या है। इन लोगों को चुनाव के समय भाजपा द्वारा कहा गया था कि चुनाव जीतने पर इन्हें पक्का किया जाएगा, मगर पक्का नहीं किया गया। जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 10 हजार सफाई कर्मी और पंजाब में 12 हजार कच्चे शिक्षकों को पक्का किया है।"

आतिशी ने भाजपा को चुनौती दी है कि वह आठ दिन में बस मार्शल को पक्का करने के लिए एलजी को प्रस्ताव भेजेंगी, भाजपा अपने एलजी से इन्हें पक्का कराए।

भाजपा के इशारे पर अनगिनत लोगों की नौकरी छीनी गई: आप

इससे पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी ने एलजी द्वारा सिविल डिफेंस वालंटियर्स (सीडीवी) के संदर्भ में मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया दी है। आप ने कहा है कि उनकी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2015 में बस मार्शल की नियुक्ति की थी, मगर भाजपा ने निम्न स्तर की राजनीति के चलते बिना किसी सुनवाई के 10 हजार से अधिक बस मार्शल को 2022 में नौकरी से निकाल दिया गया।

घर पर परफेक्ट चटनी बनाने में मदद करेंगे ये टिप्स

जब आप चटनी बना रहे हैं तो ऐसे में आप टेस्ट को बैलेंस करने पर खासतौर से फोकस करें। यूं तो हर तरह की चटनी का अपना एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर चटनी बहुत खट्टी या तीखी है तो आपको उसे खाते वक्त वह टेस्ट नहीं आएगा।

ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिन्हें चटनी खाना काफी पसंद होता है। अगर आपके खाने की थाली में चटनी परोसी जाए तो इससे स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। चटनी में भी आपको कई तरह की वैरिएशन मिलती हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार टमाटर से लेकर धनिया, पुदीना, नारियल या फिर प्याज आदि की चटनी बना सकते हैं। हालांकि, कई लोगों की यह शिकायत हाती है कि वे चटनी तो बनाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कि आप भी अपनी चटनी में वो परफेक्ट टच मिस कर रहे हों। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको ऐसे कुछ छोटे-छोटे टिप्स के बारे मे बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप परफेक्ट तरीके से चटनी बना सकते हैं-

फ्रेश हर्ब्स का करें इस्तेमाल

अगर आप चटनी के स्वाद को लाजवाब बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आप फ्रेश हर्ब्स का इस्तेमाल करें। ताजा धनिया, पुदीना व तुलसी आदि बेहद ही लाजवाब टेस्ट देते हैं। हर्ब्स के अलावा आप जिन इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे भी बासी व खराब नहीं होनी चाहिए।

टेस्ट को करें बैलेंस

जब आप चटनी बना रहे हैं तो ऐसे में आप टेस्ट को बैलेंस करने पर खासतौर से फोकस करें। यूं तो हर तरह की चटनी का अपना एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर चटनी बहुत खट्टी या तीखी है तो आपको उसे खाते वक्त वह टेस्ट नहीं आएगा। चटनी में खट्टे और मसालेदार टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी, गुड़ या शहद मिलाएं। वहीं, खट्टेपन के लिए आप इसमें नींबू का रस, इमली या सिरका आदि मिलाएं। अगर आप चटनी में तीखापन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है।

कुकिंग टेक्निक को ना करें नजरअंदाज

जब आप चटनी बनाते हैं तो आपको उसकी कुकिंग टेक्निक पर भी फोकस करना चाहिए। हर चटनी को यूं ही ब्लेंडर में पीसकर नहीं बनाया जाता है। मसलन, अगर आप दाल या मसालों वाली चटनी बना रहे हैं ता उसमें तड़का लगाना स्वाद को बढ़ाता है। इसके लिए तेल गरम करें और उसमें सरसों, जीरा या करी पत्ता डालें, जब तक कि वे चटकने न लगें। अब इसे चटनी में मिलाएं।

बढ़ते प्रदूषण में फेफड़ों के लिए किसी खजाना से कम नहीं है गुड़ का टुकड़ा, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

दिवाली के बाद से वातावरण में प्रदूषण लेवल बढ़ गया है। जिससे कई लोगो सांस संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय के जरिए खुद को स्वस्थ रख सकते है। गुड़ का सेवन किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुड़ के सेवन से ही आप अपने शरीर को हस्ट-पुस्ट रख सकते हैं। आइए जानते हैं गुड़ का सेवन करने से क्या होता है।

दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर समेत कई जगहों पर प्रदूषण स्तर बेहद खराब हो चुका है। जिसके चलते कई लोगों को सांस संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, अस्थमा मरीजों के लिए प्रदूषण का स्तर खतरा बन रहा है। ऐसे में अपनी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए गुड़ का सेवन जरुर करें। गुड़ कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यदि आपको भी प्रदूषण से परेशानी हो रही है, तो रोजाना एक गुड़ का टुकड़ा जरुर खाएं, फिर देखें इसके अनगिनत फायदे। आइए आपको बताते हैं गुड़ खाने के फायदे।

इम्यूनिटी बूस्ट होती है

गुड़ खाने से सांस संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है। इसे खाकर इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद मिलती है। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इतना ही नहीं, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली सांस संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत होना जरुरी है।

खांसी और सर्दी में लाभदायक

गुड़ खांसी और सर्दी के लिए सबसे बेहतर होता है। गुड़ की मिठास और गर्माहट वाले गुण गले की खराश को शांत करने और जलन को कम करने में मददगार होते हैं। गुड़ मिलाकर हर्बल चाय पीने से सर्दी में राहत मिलेगी।

डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार

गुड़ की मदद से शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इस सफाई प्रक्रिया से फेफड़े और वायुमार्ग स्वस्थ हो सकते हैं।

गुड़ में एंटी- एलर्जिक गुण होते हैं

गुड़ खाने पर एलर्जी से निजात मिलता है। क्योंकि, इसमें एंटी-एलर्जी गुण लक्षणों को कम करने और एलर्जी कोकम करने में मदद करता है।

प्रदूषण के असर को कम करता

दावा किया गया है कि धूल और धुंएं में काम करने वाले लोगों को रोजाना गुड़ खाना चाहिए। इनमें प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। गुड़ की मदद से टॉक्सिंस को बाहर निकालता है और शरीर की गंदगी को साफ करने में मदद करता है। ऐसे में रोजाना एक टुकड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है।

आयरन का सोर्स होता है

हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। गुड़ आयरन का एक अच्छा स्रोत है, जो ब्लड में ऑक्सजीन के फ्लो को बढ़ाता है। गुड़ शरीर में स्वस्थ ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखने में सहायक होता है।

सुबह नाश्ते में बनाएं सूजी-बेसन का हेल्दी डोसा, 5 मिनट में बनेगा क्रिस्पी डोसा

नाश्ते में हेल्दी क्या बनाएं यह हर रोज यही सवाल रहता है, आज क्या बनाएं? कुछ नया खाने के लिए सूजी-बेसन वाला डोसा घर पर जरुर बनाएं। इसे खाकर आपको काफी अच्छा लगेगा। आप भी नाश्ते में इस हेल्दी डोसा को जरुर बनाएं।

आमतौर पर हर एक गृहणी परेशान रहती है कि आज घर में क्या बनाएं। नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक यही सवाल बना रहता है कि क्या बनाएं। अगर आप भी नाश्ते के लिए कुछ हटके तलाश कर रहे हैं। तो आप नाश्ते में डोसा बना सकते हैं, अब आपके जहन में यहीं सवाल आ रहा होगा कि इसमें नया क्या है? आप ने ट्रेडिशनल डोसा उड़द की दाल और चावल वाला जरुर खाया होगा। लेकिन आप सूजी-बेसन का बना डोसा नहीं खाया होगा। इसे आप चाटनी के साथ खा सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

-1 कप - सूजी
-1/4 कप - बेसन
-1/2 कप - दही
-1 कप - पानी
-1/2 छोटा चम्मच - नमक
-1/4 छोटा चम्मच - बेकिंग सोडा
-1/2 चम्मच - नींबू का रस
- 1 चम्मच - तेल

स्टफिंग के लिए

1 बड़ा चम्मच - तेल
1/2 छोटा चम्मच - जीरा
1 हरी मिर्च
5-6 करी पत्ते
1 बड़ा प्याज
1 छोटा टमाटर
1 छोटी गाजर
50 ग्राम - पनीर
1/2 छोटा चम्मच - चाट मसाला
1/4 छोटा चम्मच - ग्राम मसाला
1/2 छोटा चम्मच - काली मिर्च पाउडर
नमक स्वाद अनुसार
1 बड़ा चम्मच - धनिया पत्ती

क्रिस्पी डोसा बनाएं

- सबसे पहले आप एक कटोरे में सूजी के साथ 1/2 कप दही मिला लें। इसके बाद 1/4 कप बेसन डाल दें, एक कप गेंहू का आटा। फिर इसनें पानी डालकर गढा मिक्सर बना लें। 5 से 10 मिनट तक बैटर से रेस्ट के लिए रख दें।

-अब स्टाफिंग के लिए एक पैन लें उसमें जीरा और हरी मिर्च डालें और फिर प्याज को डालें। करी पत्ता डालने के बाद कद्दूकस की गई गाजर डालें फिर टमाटर डालें। अब चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च पीसी हुई डाल दें। आप इस मिश्रण में थोड़ा पनीर भी डाल सकते हैं। अब आपकी स्टाफिंग तैयार है।

- इसके बाद रखा हुआ बैटर में नमक डालें और फिर उसमें पानी मिला दें। आखिर में बैकिंग सोड़ा डाले।

- इसके बाद आप एक डोसा तवा पर तेल डालकर। आंच को कम कर लें फिर तवा पर पानी के डालें फिर उसे क्लीन कर लें कपड़े से फिर आप बैटर को डाले। डोसा की तरह बनाएं और यह आपका डोसा तैयार है। नीचे दी गई वीडियों को जरुर देखें।

सेंसेटिव स्किन को इस तरह से करेंगे एक्सफोलिएट तो नहीं होगी जलन

अगर आप पहली बार किसी एक्सफोलिएंट का इस्तेमाल कर रही हैं तो यह बेहद जरूरी है कि आप पैच टेस्ट जरूर करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इससे आपकी स्किन को किसी तरह की एलर्जी या इरिटेशन की शिकायत तो नहीं हो रही है।

स्किन की केयर करने के लिए सिर्फ उसे क्लीन या मॉइश्चराइज करना ही काफी नहीं है। बल्कि आपको महीने में कम से कम दो बार उसे एक्सफोलिएट भी करना होता है। जब आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं तो इससे ना केवल डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद मिलती है, बल्कि आपकी स्किन अधिक स्मूथ व इवन टोन नजर आती है। यह सच है कि स्किन के लिए एक्सफोलिएशन जरूरी है, लेकिन एक्सफोलिएशन के दौरान आपको अपनी स्किन टाइप का भी ध्यान रखना होता है। मसलन, अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो ऐसे में आपको स्किन एक्सफोलिएशन के दौरान समस्या होती होगी। हालांकि, कुछ छोटे-छोटे टिप्स आपके बेहद काम आ सकते हैं-

सही एक्सफोलिएंट का करें चयन

अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो ऐसे में स्किन को एक्सफोलिएट करते समय आपको इंग्रीडिएंट को लेकर थोड़ा अधिक सजग होना चाहिए। हमेशा ही नेचुरल व माइल्ड इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करें। सेंसेटिव स्किन के लिए लैक्टिक एसिड और मैंडेलिक एसिड अच्छे विकल्प माने जाते हैं। आप एक सूदिंग एक्सपीरियंस के लिए ओटमील या ब्राउन शुगर जैसे फाइन और नेचुरल स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं।

जरूर करें पैच टेस्ट

अगर आप पहली बार किसी एक्सफोलिएंट का इस्तेमाल कर रही हैं तो यह बेहद जरूरी है कि आप पैच टेस्ट जरूर करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इससे आपकी स्किन को किसी तरह की एलर्जी या इरिटेशन की शिकायत तो नहीं हो रही है। कभी भी किसी नए स्क्रब को सीधे अपने पूरे चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए।

ना करें ओवर एक्सफोलिएट

कई बार हम जल्दी और बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए स्किन को ओवरएक्सफोलिएट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि, अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो आपको यह गलती करने से बचना चाहिए। सेंसेटिव स्किन के लिए आठ से दस दिन में एक बार एक्सफोलिएशन करना पर्याप्त होता है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सफोलिएशन करने से आपकी स्किन से नेचुरल ऑयल निकल सकता है और जलन हो सकती है।

एक्सफोलिएट करने के बाद करें मॉइश्चराइज़

यह एक छोटा सा टिप है, लेकिन आपको इसका खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए। अपनी सेंसेटिव स्किन को एक्सफोलिएट करने के बाद आपको हमेशा अच्छे मॉइश्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। यह ना केवल आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ-साथ एक बैरियर बनाने में मदद करता है, जिससे यह नरम और पोषित रहती है।

एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए दिल्ली से एकदम नजदीक हैं ये 10 हिल स्टेशन

दिल्ली में इस समय प्रदूषण काफी फैल रहा है। अगर आप दिल्ली की हवा में घुटन महसूस कर रहे हैं तो आप कुछ दिन के लिए घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं। दिल्ली से एकदम इन हिल स्टेशन पर जरुर घूमने जाए।

दिल्ली वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए प्राकृतिक परिवेश से भरपूर हिल स्टेशन पर जरुर घूमने जा सकते हैं, जो फेफड़ों को राहत पहुंचाएगा। प्रदूषण मुक्त छुट्टी के लिए दिल्ली के 10 बेहतरीन हिल स्टेशनों पर जरुर जाएं, ये दिल्ली के बेहद करीब है। यहां पर सुकून से भरे पल बीता सकते हैं।

मसूरी, उत्तराखंड

गौरतलब है कि मसूरी को 'पहाड़ों की रानी' के रुप में जाना जाता है। यह हिल स्टेशन हिमालय हरे-भरे जंगलों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। यहां घूमने का एक अलग ही मजा होगा।

धर्मशाला और मैकलोडगंज, हिमाचल प्रदेश

धर्मशाला और मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश के दो मुख्य हिल स्टेशन हैं, जहां धौलाधार रेंज के खूबसूरत नजारे दिखते हैं। प्रदूषण से मुफ्त इस जगह पर आप प्रकृतिक के साथ अच्छे से समय बीता सकते हैं।

चैल, हिमाचल प्रदेश

इस हिल स्टेशन की खास बात है कि यहां सबसे ऊंचे मैदान के लिए जाना जाता है। यह हिल स्टेशन की शांति और जंगल से भरे रास्ते प्रदान करता है। नवंबर के महीने में यह जगह घूमने के लिए एकदम बढ़िया है।

कसौली, हिमाचल प्रदेश

दिल्ली से कसौली बेहद नजदीक है। कसौली अपने शांत आकर्षण और औपनिवेशिक युग के कॉटेज के लिए प्रसिद्ध है। कसौली शांत प्रकृति के बीच एक सुकून भरी छुट्टी के लिए आदर्श है।

लैंसडाउन, उत्तराखंड

लैंसडाउन में एक शांत वातावरण वाला सबसे अनूठा हिल स्टेशन है। यहां पर रत्न पहाड़ियां और देवदार के जंगल है। यहां पर छुट्टियां बिताना बेहद खास हो सकता है।

कसोल, हिमाचल प्रदेश

पार्वती नदी के किनारे पर बसा है कसौल। घुमक्कड़ लोगों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां पर कैफे और सुंदर रास्तों के लिए जाना जाता है। प्रदूषण से बचने के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है।

शिमला, हिमाचल प्रदेश

ब्रिटिश काल में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला औपनिवेशिक आकर्षण, देवदार के जंगलों और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां प्रकृति के साथ अच्छे से पल बिता सकते हैं।

ऋषिकेश, उत्तराखंड

ऋषिकेश अपने खूबसूरत नदी किनारे के नजारों और शांतिपूर्ण आश्रमों के लिए जाना जाता है। यहां पर एडवेंचर लवर वालो के लिए रिवर राफ्टिंग से लेकर बंजी जंपिंग और कई तमाम एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। यहां पर आध्यात्मिक शांति चाहने वाले के लिए आदर्श जगह है।

मनाली, हिमाचल प्रदेश

मनाली अपने खूबसूरत नजारों, बर्फ से ढकी चोटियों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। यहां आप सोलंग घाटी से पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं और हिडिम्बा मंदिर भी घूमने जा सकते हैं।

नैनीताल, उत्तराखंड

नैनीताल एक आश्चार्यजनक नैनी झील के आसपास स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता और सुखद जलवायु से भरपूर है। दिल्ली के लोग प्रदूषण से बचने के लिए नैनीताल की ट्रिप पर जरुर जाएं।

क्या आप जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े ये वास्तु टिप्स

सनातन धर्म में तुलसी का पौधा का महत्व बेहद है। तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ होता है। विशेषकर कार्तिक माह में तुलसी पूजा करना अति शुभ होता है। इससे घर की मां लक्ष्मी का वास होता है, हालांकि, जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो इन वास्तु टिप्स के बारे में जरुर पता होना चाहिए।

सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पूजनीय होता है। मान्यता के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर से नकारात्मक एनर्जी दूर होती और जीवन में धन, सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके साथ ही कार्तिक माह में घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी पूजा करने शुभ फलदायी होता है। हालांकि, जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरुरी है। आइए जानते हैं तुलसी से जुड़े वास्तु टिप्स।

तुलसी के पौधे से जुड़े वास्तु टिप्स

- वास्तु के मुताबिक, तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना अति शुभ माना गया है। इसके अलावा, दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाएं। यह जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है।

- तुलसी के पौधे के पास डस्टबिन, शूज और झाड़ू रखना नहीं चाहिए।

- आप चाहे तो तुलसी के पौधे को फूलों के पौधों के पास रख सकते हैं, लेकिन इसे कैक्टस के पास न रखें। वरना घर की नेगेटिविटी को बढ़ा देता है।

- घर में विषम संख्या में 1, 3 या 5 तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। वहीं, सम संख्या में 2, 4 या 6 तुलसी के पौधे नहीं लगाना चाहिए।

- तुलसी का पौधा सदैव ऊंचा स्थान पर रखें।

- तुलसी के सुखे पौधे को घर पर कभी भी न रखें। इसको आपको जल्द ही घर से हटा दें। इसके जगह नया पौधा लगा दें। वहीं, सूखे हुई तुलसी के पौधे को पवित्र नदी या साफ पानी में प्रवाहित कर दें।

- इस बात का ध्यान रखें कि शिवजी को तुलसी का पत्ता या तुलसी दल कभी भी अर्पित नहीं करें।

'अगले 2-4 दिनों में होगी सीडीवी की तैनाती, एक हफ्ते में उपराज्यपाल के पास जाएगा प्रस्ताव', मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया पूरा प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि पिछले साल हटाए गए 10000 सिविल डिफेंस वालंटियर्स (सीडीवी) को वायु प्रदूषण से लड़ने वाली विभिन्न एजेंसियों की सहायता के लिए अगले 2-4 दिनों में फिर से तैनात किया जाएगा। सीडीवी की स्थायी नियुक्ति के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भी एक सप्ताह के भीतर उपराज्यपाल वी के सक्सेना की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को घोषणा की कि पिछले साल बस मार्शल के रूप में हटाए गए 10,000 सिविल डिफेंस वालंटियर्स (सीडीवी) की तैनाती अगले 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगी, ताकि वायु प्रदूषण से लड़ने वाली विभिन्न एजेंसियों की सहायता की जा सके। उन्होंने कहा कि सीडीवी की स्थायी नियुक्ति के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भी एक सप्ताह के भीतर उपराज्यपाल वी के सक्सेना की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री की यह घोषणा एलजी द्वारा आतिशी को लिखे गए पत्र के एक दिन बाद की गई है, जिसमें एलजी ने कहा था कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) को तुरंत फिर से नियुक्त करने के उनके आदेश के बावजूद, उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

सक्सेना ने राजनीति न करने की सलाह दी

सक्सेना ने अपने पत्र में कहा था कि बेशक, आप और आपकी पार्टी के नेता उनकी बहाली का श्रेय लेने की राजनीति करते रहेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों के कल्याण में और देरी किसी भी तरह से सही नहीं है। राजस्व और वित्त विभागों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद पिछले साल नवंबर में दिल्ली में सार्वजनिक बसों में मार्शल के रूप में काम कर रहे करीब 10,000 सीडीवी को उनके पदों से हटा दिया गया था।

अगले 2-4 दिनों में शुरू होगा आह्वान: CM आतिशी

इस मुद्दे पर आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह उनकी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ बैठक हो चुकी है। जिसमें सीडीवी को लगाने के लिए पूरी रूप रेखा तैयार की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उनका आह्वान अगले 2-4 दिनों में शुरू होगा। आतिशी ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि उसे इस मुद्दे पर अपनी घटिया राजनीति बंद करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सीडीवी की स्थायी नियुक्ति के लिए एलजी से आप सरकार के प्रस्ताव को रुकवाने का प्रयास करेगी।

CDV को काम पर लगाने की मांग कई बार हो चुकी है: CM आतिशी

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सबसे पहले भाजपा की साजिश से पिछले साल अप्रैल में सीडीवी का वेतन रोक दिया गया और बाद में भाजपा के इशारे पर उन्हें अक्टूबर, 2023 में हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जबकि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने वेतन रोके जाने और अंततः उन्हें नौकरी से हटाए जाने के बाद से आज तक सीडीवी को पूरा समर्थन दिया है, और आगे भी वे लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और उनकी सरकार सीडीवी को लगाने के लिए एलजी से कई बार मांग कर चुकी है।

'दिल्ली का चुनाव आप को जिताने का नहीं बल्कि...', अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा में लोगों से की अपील

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजौरी गार्डन से अपनी पदयात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार द्वारा किए गए कार्यों की गूंज देश के दूसरे राज्यों में सुनाई दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तीन-चार महीने बाद होने वाले चुनाव आम आदमी पार्टी को जिताने का नहीं बल्कि दिल्ली को बचाने का चुनाव है।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजौरी गार्डन से अपनी पदयात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। राजौरी गार्डन में पदयात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आप सरकार द्वारा किये गए कार्यों की गूंज देश के दूसरे राज्यों में सुनाई दे रही है। गुजरात में हमारे 5, गोवा में 2 और कश्मीर में 1 एमएलए है। पंजाब में हमारी सरकार है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन चार महीने बाद चुनाव होने हैं। यह चुनाव आम आदमी पार्टी (आप) को जिताने का नहीं बल्कि दिल्ली को बचाने का चुनाव है। याद कीजिये 2014 कि उन गर्मियों को जब दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 5500 मेगावाट होती थी और सात-सात, आठ-आठ घण्टे बिजली कटौती होती थी। अभी 8500 मेगावाट की पीक डिमांड है, फिर भी पावर कट नहीं होता।

अनाप-शनाप बिल देने की जरूरत नहीं: केजरीवाल

उन्होंने कहा कि याद कीजिये 2013 के उस दौर को जब बिजली के बिल हजारों रुपये आते थे, आज या तो जीरो या फिर 700- 800 रुपये का बिल आता है। पिछले 10 सालों में हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। ऐसे काम किये जो किसी ने नहीं किया। दूसरे कर भी नहीं सकते, या कह लें कि उनकी नीयत नहीं है। जहां-जहां गंदा पानी आ रहा है, वहां गंदा पानी आना ठीक हो जाएगा। मैं स्वयं इसकी निगरानी कर रहा हूं और हां जिनके यहां पानी के बिल अनाप-शनाप आये हैं, उन्हें बिल देने की जरूरत नहीं है।

अरविंद केजरीवाल भाजपा के दुष्प्रचार और साजिशों का पर्दाफाश करेंगे: संजय सिंह

सुषमा रानी

नई दिल्ली: 3नवंबर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आने वाले हफ्तों में दिल्ली के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पदयात्राओं की एक श्रृंखला के तहत सड़कों पर उतरेंगे। पदयात्रा का आयोजन लोगों को सीधे आप संयोजक से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, ताकि वह उनकी चिंताओं पर ध्यान दे सकें और दिल्ली के भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण साझा कर सकें। अरविंद केजरीवाल की पदयात्राओं को पहले ही जनता का जबरदस्त समर्थन मिल चुका है, पहले चरण में बड़ी संख्या में लोग अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए उमड़े हैं। इसकी घोषणा करते हुए आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि अरविंद केजरीवाल रविवार को राजौरी गार्डन में पदयात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मिल रहा अपार प्यार और समर्थन लोगों के इस विश्वास को दर्शाता है कि वे अकेले ऐसे नेता हैं, जिन्होंने पिछले एक दशक में दिल्ली में वास्तविक बदलाव लाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने दिल्ली में पहले चरण की पदयात्राओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ₹पदयात्रा के पहले चरण में अरविंद केजरीवाल को जनता का आशीर्वाद, सहयोग और प्यार मिला। वे जहां भी गए, लोगों ने अपना स्नेह व्यक्त किया और माना कि वे अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दस वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों में और माताओं और बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करके दिल्ली में बदलाव दिखाया है।" संजय सिंह ने आगे कहा, "भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को मिल रहे समर्थन के कारण उनकी पदयात्रा को बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने उनकी पदयात्रा को रोकने की कोशिश की और सुरक्षा को तोड़ते हुए उन पर हमला भी किया। इस शर्मनाक हमले का समर्थन भाजपा के प्रमुख नेताओं ने वीडियो के माध्यम से किया। चूंकि वे अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति के खिलाफ चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए वे उनकी पदयात्रा को बाधित करने के प्रयास में हिंसा का सहारा लेते हैं।" संजय सिंह ने कहा कि साजिशों और व्यवधानों से बेपरवाह अरविंद केजरीवाल अपनी पदयात्रा जारी रखेंगे, जिसका दूसरा चरण आज राजौरी गार्डन से शुरू होगा। उन्होंने कहा, "ये पदयात्राएं नवंबर और दिसंबर में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जारी रहेंगी। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति तक पहुंचना और उन्हें यह बताना है कि भाजपा किस तरह साजिशों के जरिए दिल्ली की प्रगति में बाधा डाल रही है और पिछले दस सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए जो काम किए हैं, उन्हें उजागर करना है। संजय सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि भाजपा इस पर खुली बहस करे। उन्होंने चुनौती दी कि वे अपने शासन वाले 22 राज्यों में से एक का नाम बताएं, जो मुफ्त बिजली देता हो, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देता हो या फिर ऐसे स्कूल हों, जिनमें वातानुकूलित कक्षाएँ और एथलेटिक मैदान जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएँ हों। उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया है, ऐसे स्कूल बनाए हैं जो अनुकरणीय हैं।₹ संजय सिंह ने आगे कहा, ₹जब भाजपा अरविंद केजरीवाल के शासन का मुकाबला नहीं कर पाई, तो उन्होंने हमारे नेताओं को जेल में डालने का सहारा लिया।₹ उन्होंने कहा कि कैसे भाजपा ने अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और खुद उन्हें गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली में तीन करोड़ लोगों को लाभ पहुँचाने वाली कल्याणकारी परियोजनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब भाजपा नेता छठ पूजा के लिए घाटों के निर्माण में बाधा डाल रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने त्योहार के लिए घाटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने पूछा, "यह बात लोगों तक कौन पहुंचाएगा?" और इस बात पर जोर दिया कि यह काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पदयात्रा के जरिए करेंगे।

उन्होंने सभी से बड़ी संख्या में शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा, "हम दिल्ली या अरविंद केजरीवाल की पहल को कोई नुकसान नहीं होने देंगे।" उन्होंने आगे कहा, ₹याद रखें, अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वे इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देंगे, क्योंकि 22 राज्यों में वे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा या मुफ्त चिकित्सा सेवा नहीं देते हैं।"

उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, "भाजपा हमलों और खोखले वादों के आधार पर काम करती है, जबकि हम वास्तविक शासन और जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए, भाजपा की रणनीतियों के खिलाफ सतर्क रहें। यह पदयात्रा सभी को जानकारी देगी, और मैं आपसे सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करता हूं।"

'वक्फ बोर्ड के साथ जामा मस्जिद और इसके आसपास की जगहों का हो सर्वे', दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

सुषमा रानी

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को जामा मस्जिद व इसके आसपास सर्वे-निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि जामा मस्जिद एएसआई के अधीन क्यों नहीं थी। एएसआई ने दाखिल हलफनामा में कहा कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के पर्याप्त प्रभाव होंगे।

नई दिल्ली। जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को जामा मस्जिद व इसके आसपास सर्वे-निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ एएसआइ को जामा मस्जिद का कोई स्केच या टेबल रिकार्ड पर पेश करके यह बताने को कहा है कि मस्जिद परिसर का उपयोग किन उद्देश्य के लिए हो रहा है। अदालत ने यह भी बताने को कहा कि राजस्व और दान का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है।

चार सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश

पीठ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह बताने के लिए कहा है कि क्या जामा की प्रबंध समिति के संविधान में कोई परिवर्तन किया गया है या नहीं। अदालत ने बोर्ड को जामा मस्जिद व इसके आसपास के संरक्षण या सुरक्षा के लिए सुझाव व प्रस्ताव भी पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित करते हुए अदालत ने चार सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

वक्फ बोर्ड की तरफ से संजय घोष हुए पेश

मामले पर सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने पीठ को सूचित किया कि 10 फरवरी 2015 को जारी आदेश के तहत मस्जिद की प्रबंध कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्य, महासचिव के अलावा छह सदस्य हैं। वर्तमान कमेटी के संबंध में पीठ द्वारा पूछने पर अधिवक्ता ने कहा कि कमेटी के सदस्यों की वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से साफ नहीं है और वह इस पर निर्देश लेकर जवाब देंगे।

वहीं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए स्थायी अधिवक्ता मनीष मोहन व अनिल सोनी ने कहा कि इस संबंध में एएसआइ महानिदेशक के साथ हुई बैठक में एसआईए ने कहा कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

सुहैल अहमद खान और अजय गौतम ने दायर की थी याचिका

अदालत सुहैल अहमद खान और अजय गौतम द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसमें जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी द्वारा शाही इमाम उपाधि के इस्तेमाल और उनके बेटे को नायब (उप) इमाम के रूप में नियुक्त करने पर आपत्ति जताई गई है। याचिकाओं में अधिकारियों को जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और उसके आसपास सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाओं में यह भी सवाल उठाया गया है कि जामा मस्जिद एएसआई के अधीन क्यों नहीं थी।

जामा मस्जिद के संरक्षण पर 13 साल में खर्च हुए 61.82 लाख

अधीक्षक पुरातत्वविद् ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि एएसआइ के अनुसार मूल फाइल नहीं मिल रही है। यह भी कहा कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किए बगैर एएसआई ने इसके पुनर्स्थापना और संरक्षण का काम किया। एएसआइ ने कहा कि मस्जिद के मरम्मत, नवीनीकरण, संरक्षण व अन्य कार्य में उनके द्वारा वर्ष 2007-08 से वर्ष 2021 तक कुल 61 लाख 82 हजार 816 रुपये खर्च किए गए हैं।

संरक्षित स्मारक घोषित करने के होंगे पर्याप्त प्रभाव

एएसआइ ने अदालत में दाखिल हलफनामा में कहा कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के पर्याप्त प्रभाव होंगे। संरक्षित स्मारक घोषित करने पर 100 मीटर में निर्माण वर्जित होने संबंधी निषिद्ध क्षेत्र का प्रविधान लागू होगा। इसके अलावा विनियमित में क्षेत्र (निषिद्ध क्षेत्र से परे 200 मीटर क्षेत्र) सभी निर्माण संबंधी गतिविधियों को विनियमित किया जाता है और निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। यह भी कहा कि ऐसे में स्मारक के चारों ओर 300 मीटर का क्षेत्र में केन्द्रीय सुरक्षा पर पर्याप्त प्रभाव होगा। इसके अलावा जामा मस्जिद संरक्षण वक्फ अधिनियम- 1995 के तहत दिल्ली वक्फ बोर्ड का है।

मदिरा प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली में फिर खुलेंगी शराब की प्रीमियम दुकानें; मिलेंगे सभी प्रमुख ब्रांड

सुषमा रानी

दिल्ली में अब फिर से शराब की प्रीमियम दुकानें खुलने जा रही हैं। ये दुकानें अपेक्षाकृत बड़ी होंगी और इन दुकानों में सभी प्रमुख ब्रांड उपलब्ध कराए जाएंगे। आबकारी विभाग ने प्रीमियम दुकानों को शॉपिंग मॉल में खोलने की योजना बनाई है। इस कदम से शराब की बिक्री और राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। दिल्ली में शॉपिंग मॉल में अभी 15 शराब की दुकानें खोली गई हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में अब फिर से शराब की प्रीमियम दुकानें खुलेंगी। ये दुकानें अपेक्षाकृत बड़ी होंगी, यहां पर सभी प्रमुख ब्रांड उपलब्ध कराए जाएंगे। इन दुकानों के अंदर जाकर लोग अपनी पसंद के बांड का चयन कर सकेंगे। आबकारी विभाग ने प्रीमियम दुकानों को शॉपिंग मॉल में खोलने की योजना बनाई है। शराब बेचने वाले चारों सरकारी निगमों को इस बारे में पत्र लिखा है।

दिल्ली के विभिन्न मॉल में खुली थीं 40 से ज्यादा दुकानें

2021 में इस तरह की 40 से अधिक दुकानें खोली गई थीं। दिल्ली के विभिन्न मॉल में ये दुकानें खुली थीं। दिल्ली में अभी 15 शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोली गई हैं। मगर ये प्रीमियम दुकानों के स्तर की नहीं हैं। दिल्ली के चार सरकारी निगम मिलकर शराब की बिक्री कर रहे हैं। यह सरकारी निगम मिलकर अभी 695 वाइन और बीयर की दुकानें चला रहे हैं।

शराब की दुकानों को किया जाएगा 710

आने वाले दिनों में और भी ज्यादा दुकानें खुलेंगी। जिससे बिक्री और कमाई दोनों बढ़ेगी। अब तक 950 होटलों, क्लबों और रेस्तरां के शराब लाइसेंस के रिन्यू हो गए हैं। इस साल के अंत तक शराब की दुकानों को बढ़ाकर 710 किया जाएगा। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब शराब की बड़ी दुकानें ही खोली जाएंगी, ताकि एक ही जगह शराब के कई ब्रांड आसानी से मिल जाएं।

दीवाली से पहले शराब की बिक्री का रिकॉर्ड बना

दिल्ली में दीवाली से पहले शराब की बिक्री का रिकॉर्ड बना, यहां 3.87 करोड़ से अधिक बोतलें बिकीं, जिससे आबकारी विभाग को 447.62 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह पिछले साल की तुलना में 1.18 करोड़ बोतलों की अधिक बिक्री को दर्शाता है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर तक 15 दिनों में, दिल्ली सरकार के चार निगमों द्वारा संचालित शराब की दुकानों से कुल 3.87 करोड़ बोतलें बेची गईं, जिनमें भारत में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 2.98 करोड़ बोतलें और बीयर की 89.48 लाख बोतलें शामिल हैं।

कार में भरकर ले जा रहा था अवैध शराब का भंडार, गिरफ्तार

उत्तरी जिले की वजीराबाद थाना पुलिस की टीम ने कार में भरकर अवैध शराब का भंडार ले जाते एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित चालक कार के मालिक के कहने पर अवैध शराब की आपूर्ति करता था, जिसके लिए उसे 15 हजार रुपये महीने के मिलते थे। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध शराब के कुल 12 कार्टन बरामद किए हैं और कार को भी जब्त कर लिया है।

सूचना पर पुलिस ने बिछाया था जाल

उत्तरी जिले के उपायुक्त राजा बांठिया ने बताया कि 30 अक्टूबर की देर रात पुलिस टीम तिमारपुर के इलाके में गश्त कर रही थी। लगभग 04:30 बजे गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक तस्कर कार में अवैध शराब भरकर लाने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम ने पुश्ता रोड पर जाल बिछाया और मौके से मारुति सुजुकी कार को रोका। कार चालक की पहचान अलीपुर के शकील मोहम्मद के रूप में हुई।

कार की जांच करने पर उसमें से अवैध शराब यानी फाल्कन संतरा देसी शराब की 10 पेटियां हरियाणा में बिक्री के लिए और इंपीरियल स्टाइल ब्लेंडेड व्हिस्की की दो पेटियां चंडीगढ़ में बिक्री के लिए बरामद की गईं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया।

इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए जमीन पर जल्द मिलेगा कब्जा, युवाओं के लिए ग्रेटर नोएडा में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

परिवहन विशेष न्यूज

यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 10 में औद्योगिक पार्कों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेक्टर दस के तहत प्रभावित गांव आकलपुर म्याना व मकसूदपुर गांव की जमीन अधिग्रहण की सूचना जारी कर दी गई है। तीनों गांव की कुल 243 .96 हे . जमीन सेक्टर दस के लिए अधिगृहीत की जाएगी। प्राधिकरण इस सेक्टर में पांच औद्योगिक पार्क विकसित करेगा।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक पार्कों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने सेक्टर दस के तहत प्रभावित गांव आकलपुर, म्याना व मकसूदपुर गांव की जमीन अधिग्रहण की सूचना जारी कर दी है। तीनों गांव की कुल 243.96 हे. जमीन सेक्टर दस के लिए अधिगृहीत की जाएगी। प्राधिकरण इस सेक्टर में पांच औद्योगिक पार्क विकसित करेगा। औद्योगिक निवेश के साथ रोजगार सृजन होगा।

यमुना प्राधिकरण काफी समय से सेक्टर 10 में औद्योगिक पार्कों के लिए जमीन मिलने का इंतजार कर रहा है। प्राधिकरण पहले ही 250 एकड़ जमीन किसानों से सहमति के आधार पर क्रय कर चुका है, शेष जमीन के अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन जिले में सिंचित क्षेत्र का पांच प्रतिशत से अधिक जमीन अधिग्रहण की सीमा आड़े आने के चलते प्रस्ताव पर काम आगे नहीं बढ़ पाया।

भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 19 की कार्रवाई शुरू

शासन ने पांच प्रतिशत की सीमा को बढाक़र बीस प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद सेक्टर में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट को शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 19 की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसके तहत जमीन अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के विस्थापन पर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की योजना तैयार कर उसे पर ग्रामीणों की आपत्ति एवं सुझाव लेकर उनका निस्तारण होता है, लेकिन तीनों गांव में जमीन अधिग्रहण से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। धारा 19 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजा वितरण और जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सेक्टर दस में आकलपुर गांव की 45.69 हे., म्याना गांव की 165.25 हे. व मकसूदपुर गांव 33.06 हे. जमीन अधिगृहण की जा रही है।

इस जमीन पर प्राधिकरण की लेदर पार्क, ईवी पार्क, प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क समेत पांच औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने पर औद्योगिक पार्कों के लिए भूखंड योजना निकाली जाएगी।

कार्गो टर्मिनल को सड़क कनेक्टिविटी के लिए भी जल्द मिलेगी जमीन

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल को यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी के लिए जमीन अधिगृहीत की जा रही है। इसके लिए रोही, पारोही, दस्तमपुर व रन्हेरा गांव की 6.82 हे.जमीन अधिगृहीत की जा रही है।

इस जमीन से भी गांव का कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। इसलिए जमीन पर जल्द कब्जा मिलने की उम्मीद है। जमीन मिलने पर एयरपोर्ट की उत्तर दिशा में तीस मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी।

इसके निर्माण को लेकर यमुना प्राधिकरण व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के बीच पहले ही अनुबंध हो चुका है। जमीन पर कब्जा मिलने की एनएचएआइ निर्माण कार्य शुरू कर देगा। सड़क बनने से यमुना एक्सप्रेस वे से आने वाले माल वाहक वाहन कार्गो टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे।

भूखंड योजना में पंजीकरण का आज अंतिम दिन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बीपीओ और आइटीईएस भूखंड योजना में पंजीकरण का रविवार को अंतिम दिन है। आठ भूखंड की योजना में चार नवंबर तक दस्तावेज जमा कराने होंगे। भूखंडों का आवंटन नीलामी से होगा। स्टार्टअप को मौका देने के साथ योजना के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नालेज पार्क पांच में आठ भूखंडों योजना निकाली थी।

इस योजना में आइटी, बीपीओ और आइटीईएस क्षेत्र की कंपनियों को नीलामी से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इसमें दो भूखंड 500 वर्गमीटर और छह भूखंड 1000-1000 वर्गमीटर के हैं। प्राधिकरण के ओएसडी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि योजना में पंजीकरण और प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तीन नवंबर है। चार नवंबर को प्रपत्र जमा करने होंगे। प्रपत्रों की जांच करने के बाद नीलामी के माध्यम से भूखंड आवंटित किए जाएंगे। आवंटियों को एक माह में कब्जा दे दिया जाएगा। योजना के जरिये ग्रेटर नोएडा में निवेश के साथ रोजगार सृजन होगा।

गाजियाबाद में बढ़ेगा सियासी पारा, 6 नवंबर को आएंगे CM योगी; अखिलेश यादव भी करेंगे प्रचार

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो चुकी है। त्योहार बाद अब छह नवंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए शहर आएंगे। इस दौरान प्रताप विहार में रोड शो कर सकते हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गाजियाबाद आ सकते हैं। शहर सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, इसके लिए 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। त्योहारों की छुट्टी खत्म होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा प्रचार तेज किया जाएगा। भाजपा की ओर से उपचुनाव का तापमान बढ़ाने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ छह नवंबर को गाजियाबाद आएंगे।

भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा के पक्ष में वह प्रताप विहार में रोड शो कर मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद रोड शो को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी जुट गए हैं।

प्रताप विहार में किया जाएगा रोड शो

उनका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोड शो में शामिल किया जाए। यह पहली बार होगा जब प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री द्वारा प्रताप विहार में रोड शो किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले चार नवंबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद आएंगे। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लोगों को संबोधित करेंगे और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

योगी के बाद अखिलेश के आने की भी चर्चा

भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद आने के बाद सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गाजियाबाद आ सकते हैं।

बसपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बसपा प्रमुख व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी यहां आ सकती हैं। चुनाव की तिथि जैसे -जैसे करीब आएगी, यहां पर चुनाव प्रचार और कद्दावर नेताओं का आगमन भी बढ़ेगा। अब देखना यह है कि किस पार्टी के नेता मतदाताओं को साधने में सफल होते हैं, जिससे कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिल सके।

विस उपचुनाव में सपा बना रही सभी बूथों को जीतने की रणनीति

गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार की है, जिसमें सपा ने इस बार गाजियाबाद सीट पर लाइनपार विजय नगर के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस चुनाव में सपा पिछले काफी समय से पदासीन मेयर, विधायक, मंत्री और सांसद के रहते हुए लाइनपार का पिछड़ापन दूर न करने पर भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है।

गाजियाबाद विधानसभा सीट का दायरा 32 वार्ड तक सिमटा है। इसमें 58 सेक्टर और 506 बूथ शामिल हैं। सपा ने उप चुनाव में इस सीट को जीतने के लिए मुख्य संगठन की टीम के साथ बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और उनकी टीम, समस्त प्रकोष्ठ व उनकी टीम के साथ प्रत्याशी की अपनी टीम को जिम्मेदारी दी है।

महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि डोर टू डोर मतदाताओं के पास पहुंचने का लक्ष्य रखा है। लाइनपार की तमाम समस्याओं और उनके समाधान का मुद्दा इस बार के चुनाव में काफी अहम है।

"विकास के हिसाब से पिछड़ा है गाजियाबाद"

विजय नगर के निवासी रविन चौधरी का कहना है कि लाइनपार का इलाका गाजियाबाद में आता है, लेकिन विकास के हिसाब से शहर से काफी पिछड़ा हुआ है। इसके विकास को लेकर कभी किसी ने गंभीरता से काम नहीं किया। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं, लेकिन जीत हार के बाद संघर्ष और समाधान कराने की कोई नहीं सोचता। जीत-हार के बाद अपने क्षेत्र के विकास के वादे को नहीं भूलना चाहिए।

नोएडा के 55 गांवों में लाइब्रेरी बनाएगा प्राधिकरण, पुस्तकालय में होंगी कई सुविधाएं

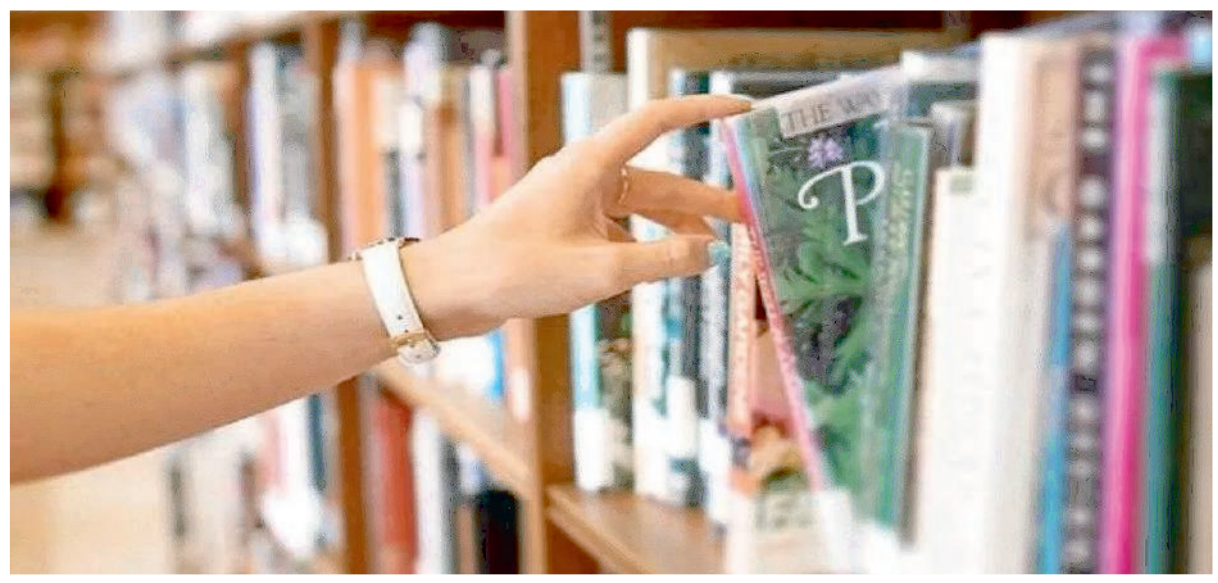

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। यमुना प्राधिकरण में शामिल हो चुके 55 गांवों के पंचायत घर को अब पुस्तकालय में बदला जाएगा। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें कंप्यूटर वाइफाई फर्नीचर पुस्तक ई-पुस्तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक आदि मिलेंगी। इन गांवों में बनेंगी लाइब्रेरी।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में शामिल हो चुके 55 गांवों के पंचायत घर पुस्तकालय में तब्दील होंगे। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के प्रस्ताव को यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह ने अपनी स्वीकृति दे दी है।

पंचायत घरों को पुस्तकालय बनाने से प्राधिकरण (Yamuna Authority) के करोड़ों रुपये की बचत होगी। वहीं कम समय में ग्रामीणों को पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पुस्तकालय में ई पुस्तक से लेकर वाइफाइ की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

96 गांवों में पुस्तकालय बनाने की हुई थी घोषणा

यमुना प्राधिकरण अपने अधिसूचित गांवों में ग्रामीणों की मांग पर पुस्तकालय का निर्माण करा रहा है। इसमें भवन निर्माण से लेकर फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर, वाइफाई, समाचार पत्र, पुस्तक व ई पुस्तक की सुविधा दी जा रही है। प्राधिकरण सीईओ ने 15 अगस्त को डूंगरपुर रीलखा गांव में पुस्तकालय का लोकार्पण किया था। इसके साथ पहले फेज के सभी 96 गांवों में पुस्तकालय बनाने की घोषणा की थी।

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने 55 गांवों में पंचायत घरों का सर्वे कराने के बाद इन्हें पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव दिया, इसे प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया। पंचायती राज व्यवस्था समाप्त होने के बाद गांवों में पंचायत घर का खास उपयोग नहीं रह गया है। अनुपयोगी होने व देखरेख के अभाव में पंचायत घर खंडहर में बदलने लगे हैं।

सर्वे में सामने आया है कि पंचायत घर में मामूली मरम्मत कार्य कराने के बाद उन्हें पुस्तकालय के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। इन पंचायत घरों में खड़की, फर्श, छत, दरवाजे, बिजली की वायरिंग आदि की मरम्मत की जरूरत है। पुस्तकालय के लिए नया भवन बनाने पर होने वाला खर्च बचने के साथ ही इसके लिए जमीन तलाशने की समस्या का भी सामना नहीं कर करना पड़ेगा।

डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने 55 गांव की सूची सौंपकर गांव के पंचायत घरों को पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण इसके लिए सहमत है। जल्द ही इन गांवों में पंचायत घरों को पुस्तकालय बनाने का काम शुरू किया जाएगा।

पुस्तकालय में यह होंगी सुविधाएं

कंप्यूटर, वाइफाइ, फर्नीचर, पुस्तक, ई पुस्तक, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, पुस्तकालय की देखरेख के लिए कर्मचारी

इन गांवों में पंचायत घर बनेंगे पुस्तकालय

मकनपुर बांगर, निलोनी शाहपुर, चक, कादलपुर, खेरली, गढ़ाना, पारसौल, ठसराना, मूंजखेड़ा, सलारपुर, डेरीन गुजरान, बल्लू खेड़ा, लतीफपुर, आदि गांव शामिल हैं।

अपनी सीट बैल्ट बांध लें, आगे उथल-पुथल है

पी. चिदम्बरम

आर.बी.आई. का मौद्रिक नीति वक्तव्य एक कारण से सुर्खियों में रहता है- नीतिगत रेपो दर। रेपो दर वह ब्याज दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक (आर.बी.आई.) वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियों के बदले में धन उधार देगा, इस वादे के साथ कि वह बाद में प्रतिभूतियों को फिर से...

आर.बी.आई. का मौद्रिक नीति वक्तव्य एक कारण से सुर्खियों में रहता है- नीतिगत रेपो दर। रेपो दर वह ब्याज दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक (आर.बी.आई.) वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियों के बदले में धन उधार देगा, इस वादे के साथ कि वह बाद में प्रतिभूतियों को फिर से खरीद लेगा। अगर रेपो दर कम हो जाती है तो उधारकर्त्ता खुश होते हैं। क्योंकि इसका मतलब है कि बैंक कम दर पर उधार ले सकते हैं और परिणामस्वरूप कम दर पर उधार दे सकते हैं। मुद्रास्फीति पर नजर रखने वाले खुश होते हैं, अगर रेपो दर बढ़ाई जाती है, क्योंकि माना जाता है कि यह दर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का साधन है। यदि रेपो दर अपरिवर्तित रहती है, तो यह सभी हितधारकों को अनुमान लगाने पर मजबूर कर देगी।

गवर्नर और रेपो दर : 27 मार्च, 2020 को रेपो दर 5.0 प्रतिशत से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दी गई। यह एक बड़ी कटौती थी और इस आधार पर उचित ठहराई गई थी कि कोविड-प्रभावित अर्थव्यवस्था को मंदी का खतरा था। यह 26 महीनों तक 4.0 प्रतिशत पर बनी रही। जब कोविड का प्रकोप कम हुआ और अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखे, तो मई 2022 में रेपो दर में भारी वृद्धि कर इसे 4.40 प्रतिशत कर दिया गया। जाहिर तौर पर मुद्रास्फीति की आशंकाओं को काबू में करने के लिए।

फरवरी 2023 तक यह लगातार 6.50 प्रतिशत पर पहुंच गई, जहां यह 20 महीने तक बनी रही। मई 2022 से, गवर्नर श्री शक्तिकांत दास मुद्रास्फीति-योद्धा रहे हैं, लेकिन अपरिवर्तित रेपो दर का मतलब है कि आर.बी.आई. अभी तक मुद्रास्फीति को काबू में करने में सफल नहीं हुआ। कोई भी गवर्नर सभी हितधारकों को खुश नहीं कर सकता। यू.पी.ए. सरकार ने गवर्नर का बोझ सांझा करने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति (एम.पी.सी.) का गठन किया, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी गवर्नर का है।

गवर्नर को विकास और मुद्रास्फीति को संतुलित करना और निर्णय लेना होता है। मुद्रास्फीति अभी भी 4 प्रतिशत की लक्ष्य दर की ओर नहीं बढ़ रही। खाद्य और ईंधन की कीमतें मामले को जटिल बनाती हैं। दोनों ही ब्याज दरों में बदलाव का जवाब नहीं देतीं। गवर्नर ने तर्क दिया कि रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का औचित्य था। इसके विपरीत तर्क यह है कि उच्च रेपो दर अर्थव्यवस्था की विकास दर को कम करने का प्रभाव डालती है।

विकास और मुद्रास्फीति : विकास और मुद्रास्फीति आर.बी.आई. के साथ-साथ सरकार की दो प्राथमिक ङ्क्षचताएं हैं। श्री शक्तिकांत दास ने चालू वर्ष में 7.5 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर की सराहना की, लेकिन मुद्रास्फीति को भी चिन्हित किया, जिसके 4.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची- सितंबर 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.49 प्रतिशत अधिक थी। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक 9.24 प्रतिशत रहा।

अक्तूबर 2024 में जारी आर.बी.आई. की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में दोनों विषयों पर और अधिक कहा गया है। रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों को पढऩे के बाद 'विकास के दृष्टिकोण' पर कहा गया है- 'अनिश्चित वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, भू-राजनीतिक संघर्ष, आपूर्त श्रृंखला पर बढ़ते दबाव और अस्थिर वैश्विक वित्तीय स्थितियां, हालांकि नकारात्मक पक्ष के दृष्टिकोण पर भारी असर डालती हैं।'' रिपोर्ट में अन्य कारकों, जैसे 'भू-आर्थिक विखंडन, वैश्विक मांग में कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार मौसम संबंधी गड़बड़ी' को भी चिन्हित किया गया है।

'मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण' पर रिपोर्ट में जोखिमों की पहचान 'बढ़ते वैश्विक आपूर्त दबाव, प्रतिकूल मौसम की घटनाएं, वर्षा का असमान वितरण, लंबे समय तक भू-राजनीतिक संघर्ष और उसके परिणामस्वरूप आपूर्त श्रृंखला में व्यवधान, खाद्य और धातु की कीमतों में उछाल, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं' के रूप में की गई है। ये 10 अलग-अलग नकारात्मक जोखिम हैं।

प्रतिकूल परिस्थितियां : वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में एक स्पष्ट आकलन है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को 'संतोषजनक' बताया, लेकिन चेतावनी दी कि 'अंतर्निहित मांग स्थितियों पर नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक संघर्षों में वृद्धि, आर्थिक विखंडन में वृद्धि और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजारों में उच्च मूल्यांकन से विकास के लिए जोखिम उत्पन्न होते हैं।

एन.सी.ए.ई.आर. की मासिक आर्थिक समीक्षा संतुलित है। सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने के बाद, समीक्षा ने नकारात्मक पहलुओं की ओर इशारा किया- बैंक ऋण में कमी; व्यक्तिगत ऋण, सेवाओं, कृषि और उद्योग में मंदी; रुपए का अवमूल्यन और एफ.पी.आई. प्रवाह में कमी।

मेरे विचार में, पक्षी की नजर से देखने का तरीका कीड़े की नजर से बहुत अलग है। जबकि पूर्व में मैक्रो-इकोनॉमी को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, यह बाद वाला है जो आम लोगों के लाभ और दर्द को दर्शाता है। लोगों की ङ्क्षचताएं हैं बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, स्थिर वेतन, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता, अत्यधिक विनियमन, जी.एस.टी. और कठोर जी.एस.टी. प्रशासन, शिक्षा की खराब गुणवत्ता, महंगी चिकित्सा सेवाएं, बेपरवाह नौकरशाही और सार्वजनिक व्यय, जो अमीरों का पक्ष लेते हैं और गरीबों को निचोड़ते हैं।

उपरोक्त के साथ-साथ, कई अन्य चीजें भी गलत हो सकती हैं: मध्य-पूर्व में क्रूर युद्ध और भी देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध में नाटो देश भी शामिल हो सकते हैं। मणिपुर में फिर से आग लग सकती है। महाराष्ट्र के चुनाव में कोई आश्चर्य हो सकता है। चीन-ताइवान या दक्षिण कोरिया-उत्तर कोरिया हॉटस्पॉट बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं।

देश में 'फर्जी' का बोलबाला पकड़े जा रहे नकली 'अधिकारी' और 'जज'

अब तक तो देश में नकली खाद्य पदार्थों, दवाइयों, खादों, कीटनाशकों, करंसी आदि की बातें सुनी जाती थीं, पर अब यह बीमारी विभिन्न विभागों के नकली अधिकारियों, नकली जजों, ई.डी. और पुलिस अधिकारियों आदि तक पहुंच गई है।

अब तक तो देश में नकली खाद्य पदार्थों, दवाइयों, खादों, कीटनाशकों, करंसी आदि की बातें सुनी जाती थीं, पर अब यह बीमारी विभिन्न विभागों के नकली अधिकारियों, नकली जजों, ई.डी. और पुलिस अधिकारियों आदि तक पहुंच गई है जिसके 3 महीनों के उदाहरण निम्न में दर्ज हैं :

● 10 अगस्त को दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने 2 पुलिस कर्मचारियों को नकली आयकर अधिकारी बन कर एक बिजनैसमैन के घर छापा मारने और रिश्वत के रूप में मोटी रकम मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया।

● 23 अगस्त को सागर (मध्य प्रदेश) में स्वयं को कभी 'इकोनॉमिक आफैंसेज विंग' (ई.ओ.डब्ल्यू.) का असिस्टैंट डायरैक्टर और कभी कोई अन्य अधिकारी बताकर सरकारी कर्मचारियों तथा आम लोगों को ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

● 30 अगस्त को भारत की गुप्तचर संस्था 'अनुसंधान और विश्लेषण विंग' (रॉ) में स्वयं को डी.आई.जी. लैवल का आई.पी.एस. अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाने वाले इंद्रनील राय नामक ठग को नोएडा (उत्तर प्रदेश) की कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह एक होटल में परिवार सहित 25 दिनों से ठहरा हुआ था और पैसे मांगने पर फर्जी आई.डी. दिखाकर होटल के मैनेजर पर रौब डाल रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने स्वीकार किया कि वह फर्जी अधिकारी बन कर होटलों में रहता और मुफ्त में खाता-पीता था।

● 16 सितम्बर को कोरबा (छत्तीसगढ़) में आधी रात के समय नकली ट्रैफिक इंस्पैक्टर (टी.आई.) और पुलिस अधिकारी बन कर वहां से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध रूप से एंट्री फीस वसूल करने के आरोप में एक कोयला खदान के 4 अधिकारियों और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया।

● 1 अक्तूबर को सूरत (गुजरात) में स्वयं को कस्टम का वरिष्ठ अधिकारी बताकर 7 लोगों से 15.12 लाख रुपए ठगने के आरोप में एक जालसाज को पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया।

● 22 अक्तूबर को अहमदाबाद (गुजरात) में फर्जी अदालत चला कर आदेश पारित करने वाले 'मोरिस सैमुअल' नामक वकील को हिरासत में लिया गया। वह 5 वर्षों से विशेष रूप से गांधीनगर क्षेत्र में आने वाली भूमि के मामलों में फर्जी आदेश पारित करता था जिसके लिए उसने अहमदाबाद में एक फर्जी अदालत भी कायम कर रखी थी। उसने अपने दफ्तर को बिल्कुल अदालत की तरह बना रखा था और उसके साथी अदालत के कर्मचारी या वकील के रूप में खड़े होकर यह जाहिर करते थे कि कार्रवाई असली है। इस तरकीब से 'मोरिस सैमुअल' ने 11 से ज्यादा मामलों में अपने ही पक्ष में आर्डर पारित किए।

● 23 अक्तूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 'विशेष कार्य अधिकारी' (ओ.एस.डी.) बन कर पुलिस के वरिष्ठों अधिकारियों को धमकाने तथा उन पर अपने परिचितों को बृजपुरी इलाके में एक विवादित सम्पत्ति का स्वामित्व दिलाने में मदद करने के लिए दबाव बनाने के आरोप में एक जालसाज नवीन कुमार सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया।

● 25 अक्तूबर को ही प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के अधिकारी बन कर एक व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की वसूली करने के प्रयास में दिल्ली पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया।

● और अब 31 अक्तूबर को चूरू (राजस्थान) जिले की साहवा थाना पुलिस ने बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर लगभग 13 लाख रुपए की ठगी करने वाली देवगढ़ निवासी अंजू शर्मा नामक फर्जी महिला थानेदार को गिरफ्तार किया।

वह खुद को दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक बताकर 3 वर्ष से दिल्ली-जयपुर और हरियाणा में सुविधाओं का लाभ उठा रही थी। उसके पास से फर्जी पुलिस वर्दी, आई.डी. कार्ड और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। उक्त उदाहरणों से स्पष्टां है कि देश में जालसाजी किस कदर बढ़ रही है। अतः जहां लोगों को ऐसे शातिरों से सतर्क रहने की जरूरत है, वहीं ऐसे समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि वे देश और समाज से धोखा न कर सकें।

-:सौजन्य:-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

रिज़्टा ने एथर के बाजार की बढ़ाई हिस्सेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

एथर एनर्जी ने अक्टूबर 2024 में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की सूचना दी, जिसमें पूरे भारत में 20,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर भेजे गए, जो अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री है। इस महीने एथर की सफलता काफी हद तक उसके नए स्कूटर, रिज्टा की लोकप्रियता से प्रेरित थी, जिसकी कुल बिक्री में 60-70% हिस्सेदारी थी और इसने ब्रांड की पहुँच को उसके दक्षिणी गढ़ से आगे बढ़ाकर दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के बाज़ारों तक पहुँचाया। यह उपलब्धि एथर की सितंबर की बिक्री की गति पर आधारित है, जहाँ कंपनी ने राष्ट्रीय बाज़ार हिस्सेदारी का 14.3% हिस्सा हासिल किया, जो जुलाई में 7.9% से काफ़ी ज़्यादा है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में उछाल के साथ, अक्टूबर में इस क्षेत्र में साल-दर-साल 70% की वृद्धि देखी गई, एथर रणनीतिक रूप से विस्तार कर रहा है। कंपनी के बढ़ते बुनियादी ढांचे में पूरे भारत में 231 अनुभव केंद्र और 2,500 फास्ट-चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एथर एनर्जी ने तमिलनाडु में अपनी मौजूदा होसुर सुविधा के पूरक के रूप में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में दूसरा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।

यह मजबूत बाजार प्रदर्शन एथर की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की योजना के अनुरूप है, जिससे लगभग 4,500 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में कंपनी के विकास के अगले चरण का समर्थन करेगा।

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में 20 अरब डॉलर का करेंगे निवेश : एसएंडपी रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार सहायक नीतियों और विस्तारित उत्पाद पेशकशों से 2024 से 2026 तक प्रमुख दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 20% से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि होने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि रेटेड कार निर्माता अगले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में ईवी उत्पादन पर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे चीनी कार निर्माता ईवी बाजार में विस्तार और क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, उनके व्यावसायिक अवसर संबंधित वित्तीय जोखिमों से अधिक होने की संभावना है। जापानी कार निर्माताओं को ईवी प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार हिस्सेदारी में धीरे-धीरे कमी का सामना करना पड़ रहा है, आंतरिक दहन इंजन और हाइब्रिड वाहनों में उनकी ताकत अगले तीन से पांच वर्षों में इस क्षेत्र में उनकी अग्रणी बिक्री स्थिति का समर्थन करना जारी रखेगी।

चीनी ईवी निर्माता एसएसईए बाज़ार के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्ज़ा करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में पहली बार कार खरीदने वालों की बड़ी आबादी, जो आम तौर पर ब्रांड पहचान से ज़्यादा किफ़ायतीपन को प्राथमिकता देती है, इन निर्माताओं के लिए अपनी उपस्थिति स्थापित करने का एक आकर्षक अवसर प्रस्तुत करती है।

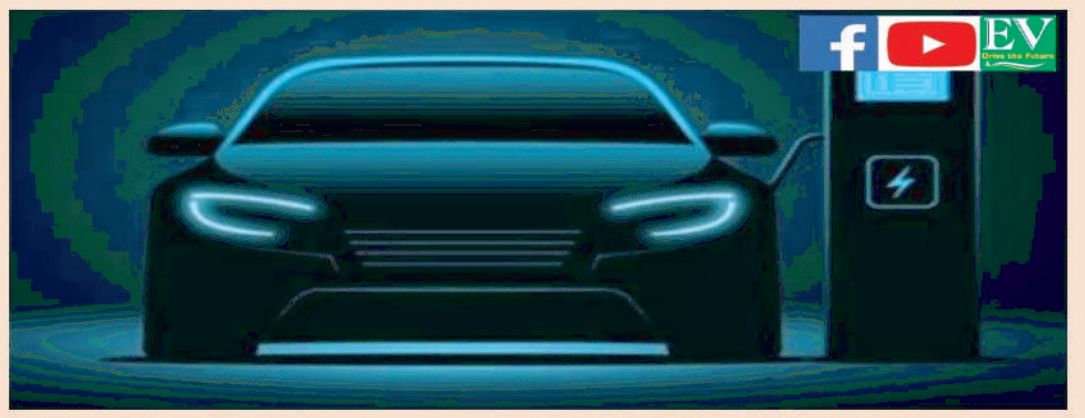

रिपोर्ट के अनुसार कोरियाई वाहन निर्माता इंडोनेशिया में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं, रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से ईवी उत्पादन सुविधाएं स्थापित कर रहे हैं। बैटरी सेल उत्पादन के लिए एलजी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ उल्लेखनीय सहयोग एक व्यापक ईवी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये इंडोनेशियाई सुविधाएं व्यापक SSEA बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय ईवी सेक्टर में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें घरेलू कंपनी टाटा मोटर्स सबसे आगे है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी के रूप में, टाटा मोटर्स ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक यात्री वाहनों में 18-20% बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। ईवी सेक्टर के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता तमिलनाडु में एक नए ईवी प्लांट में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की हाल ही में की गई घोषणा में स्पष्ट है।

मूल कंपनी टाटा संस गुजरात में लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में निवेश करके अपनी ईवी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रही है। 20 गीगावाट घंटे की शुरुआती क्षमता के साथ, इस सुविधा का उद्देश्य स्थानीय ईवी आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

एसएसईए क्षेत्र वैश्विक ईवी निर्माताओं के लिए विकास बाजार और परीक्षण स्थल दोनों के रूप में उभर रहा है। जबकि बाजार की संभावना महत्वपूर्ण है, उद्योग विशेषज्ञों को अगले तीन से पांच वर्षों में तीव्र प्रतिस्पर्धा की आशंका है, जिससे संभवतः आपूर्ति अधिशेष और मूल्य युद्ध हो सकते हैं जैसा कि पहले चीन में देखा गया था।

रिपोर्ट के अनुसार एसएसईए में ईवी परिदृश्य के निरंतर विकसित होने के कारण निर्माताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय अनुशासन बनाए रखें तथा विस्तार जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए स्थानीय भागीदारी का लाभ उठाएं। क्षेत्र का एक प्रमुख ईवी हब में परिवर्तन अपरिहार्य प्रतीत होता है, हालांकि इस मार्ग में शामिल सभी खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी चुनौतियाँ शामिल हो सकती हैं।

एसएसईए के ईवी बाजार में उभरता परिदृश्य वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बाजार के परिपक्व होने के साथ संभावित विजेता और हारने वाले उभर रहे हैं।

होंडा और असाही कासेई ने बैटरी सेपरेटर के लिए बनाया संयुक्त उद्यम

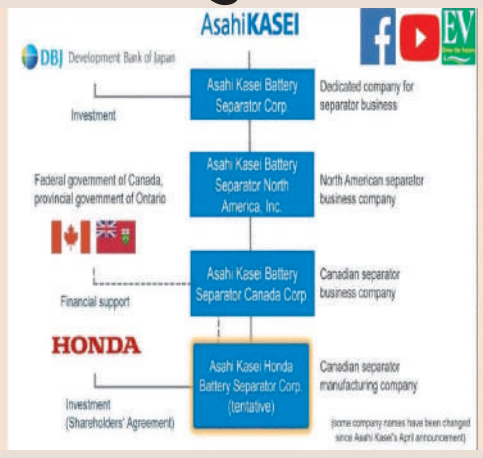

परिवहन विशेष न्यूज

असाही कासेई कॉर्पोरेशन और होंडा मोटर कंपनी ने कनाडा में एक नया संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिसमें असाही कासेई की सहायक कंपनी ई-मटेरियल्स कनाडा कॉर्पोरेशन को असाही कासेई होंडा बैटरी सेपरेटर कॉर्पोरेशन के नाम से एक सहयोगी व्यवसाय में परिवर्तित किया जाएगा। यह उद्यम लिथियम-आयन बैटरी सेपरेटर के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी में एक महत्वपूर्ण घटक है।

समझौते की शर्तों के तहत, होंडा तीसरे पक्ष के शेयर आवंटन के माध्यम से ई-मटेरियल्स में 25% हिस्सेदारी हासिल करेगी, जिसमें C$417 मिलियन (लगभग US$300 मिलियन) का कुल निवेश होगा। इस सहयोग का उद्देश्य होंडा की इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए आवश्यक बैटरी स्थायित्व और प्रदर्शन में सुधार के लिए होंडा की विद्युतीकरण पहलों के साथ उन्नत सामग्री प्रौद्योगिकियों में असाही कासेई की विशेषज्ञता को मिलाना है।

संयुक्त उद्यम के 2025 की शुरुआत में चालू होने की उम्मीद है, विनियामक अनुमोदन लंबित है, और यह उत्तरी अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए होंडा की व्यापक रणनीति का समर्थन करेगा, जो 2050 तक कार्बन तटस्थता लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। असाही कासेई बैटरी सेपरेटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रयू तानिगुची ने कहा कि यह साझेदारी उत्तरी अमेरिका की बैटरी विभाजक आपूर्ति को बढ़ाने और ईवी उत्पादन में स्थिरता के प्रयासों में योगदान करने के लिए दोनों कंपनियों की तकनीकी शक्तियों का लाभ उठाएगी।

यह कदम होंडा के दीर्घकालिक विद्युतीकरण लक्ष्यों के अनुरूप है, जो ईवी बैटरी सामग्री के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है और बैटरी प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देता है। उच्च गुणवत्ता वाले विभाजकों की स्थिर आपूर्ति के साथ, संयुक्त उद्यम क्षेत्र के ऊर्जा संक्रमण और बढ़ते ईवी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने की स्थिति में है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कृषि-खाद्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान, ब्रिक-नाबी का किया उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और अन्य प्रमुख विभागों के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान-ब्रिक-राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान (ब्रिक-एनएबीआई) के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि-खाद्य क्षेत्र को बदलना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ₹विकसित भारत₹ के दृष्टिकोण में योगदान देता है।

इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं और हितधारकों की एक सभा को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण के लिए ये लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। डॉ. सिंह ने मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित किया, उन्होंने बायोई3 नीति के शुभारंभ का हवाला दिया, जो अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण को बढ़ावा देने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देती है। उन्होंने कहा, ₹जैव प्रौद्योगिकी और सिंथेटिक उत्पादन न केवल कृषि को बदल देगा, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति में भारत की स्थिति को भी फिर से परिभाषित करेगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक विशेष जैव प्रौद्योगिकी नीति को लागू करने वाले पहले देशों में से एक है। यह बदलाव टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देगा, जिससे भारत को पारंपरिक विनिर्माण से उन्नत, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सिंथेटिक उत्पादन की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने भारत की आर्थिक उन्नति का श्रेय ₹नाजुक पाँच₹ अर्थव्यवस्थाओं में से एक से दुनिया की शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने को दिया, जिसका श्रेय सरकार के विज्ञान-संचालित विकास पर ध्यान केंद्रित करने को दिया जाता है।

नवनिर्मित BRIC-राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI) और सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग (CIAB) के बीच रणनीतिक विलय का परिणाम है। संस्थान का उद्देश्य अनुसंधान और व्यावसायीकरण के बीच की खाई को पाटना, पायलट-स्केल उत्पादन की सुविधा प्रदान करना और बाजार में नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को लाना है।

डॉ. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इस एकीकरण से कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उच्च उपज वाली, रोग प्रतिरोधी फसलों के साथ-साथ जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों का निर्माण होगा। ये प्रगति किसानों की आय को दोगुना करने और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।

नए संस्थान की प्रमुख विशेषताओं में से एक बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना है। यह सहयोगी केंद्र कृषि, खाद्य और जैव प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे युवा उद्यमियों, महिलाओं और किसानों को उद्योग भागीदारी और नवाचार नेटवर्क तक पहुँचने में मदद मिलती है। इनक्यूबेशन सेंटर का उद्देश्य कृषि-खाद्य नवाचारों के व्यावसायीकरण में तेजी लाना और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

डॉ. सिंह ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और उद्योग जगत के खिलाड़ियों से बाजार की संभावनाओं को खोलने और भारत के युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करने के लिए ऐसी पहलों में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने बायोनेस्ट पहल को व्यापक "मेक इन इंडिया" विजन का हिस्सा बताया, जो आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। भविष्य को देखते हुए, डॉ. सिंह ने दिसंबर 2024 में होने वाली बायोमैन्युफैक्चरिंग कार्यशाला 1.0 के शुभारंभ की घोषणा की। कार्यशाला कृषि, खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा क्षेत्रों में बायोमैन्युफैक्चरिंग के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो टिकाऊ उत्पादन के लिए जैविक प्रणालियों का लाभ उठाने वाली अत्याधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। यह कार्यक्रम शोधकर्ताओं और उद्योग के पेशेवरों को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाएगा, जो बायोई3 नीति के उद्देश्यों और पर्यावरण के अनुकूल नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

अपने संबोधन के दौरान डॉ. सिंह ने भारतीय वैज्ञानिकों के प्रतिभा पलायन के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने युवा शोधकर्ताओं और उद्यमियों से भारत में रहने का आग्रह किया, देश के बढ़ते वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि अब यह वैश्विक संस्थानों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी विशेषज्ञता का निर्माण विज्ञान और नवाचार में भारत के वैश्विक प्रभाव को मजबूत करेगा।

ब्रिक-राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान का उद्घाटन भारत की विज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बायोई3 और बायोनेस्ट जैसी पहलों के साथ, भारत का लक्ष्य ज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में खुद को स्थापित करना है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास में योगदान देता है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने वाला जादुई स्विच

परिवहन विशेष न्यूज

1983 में भारत की सड़कों पर एक शांत क्रांति हो रही थी। 14 दिसंबर को मारुति 800 को बाजार में उतारा गया, जिसने मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती कीमत पर आंतरिक दहन इंजन वाहन उपलब्ध कराया। बड़े सपनों वाली इस छोटी कार ने ICE वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया और ऑटो उद्योग की गतिशीलता को बदल दिया।

40 साल से भी ज़्यादा समय के बाद, सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर में दूसरी बार वापसी की योजना बना रही है, इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के ज़रिए। इस रणनीति का एक हिस्सा 30@30 है, जिसका लक्ष्य 2030 तक नई बिक्री में ईवी की 30% हिस्सेदारी हासिल करना है। ऑटोमेकर पहले से ही इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं; कई ने आईसीई वाहनों के लिए चरणबद्ध तरीके से समाप्ति की तारीखों की घोषणा की है।

भारत में सुजुकी को उम्मीद है कि 2030 तक उसकी बिक्री का 15% हिस्सा ईवी से आएगा। टाटा मोटर्स की योजना उसी वर्ष तक वैश्विक स्तर पर ईवी से 50% बिक्री हासिल करने की है। सितंबर में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के एक सम्मेलन में, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2030 तक ईवी बाजार में 1 करोड़ वार्षिक बिक्री होगी। लेकिन इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा।

बाधा कोर्स का सामना करना

अन्य पहलों के अलावा, 2020 में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का विजन भी शामिल है। सरकार ने ईवी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी शुरू की और मेक इन इंडिया पहल को गति देने के लिए मार्च 2024 में ईवी विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।

योजनाओं की भरमार के अलावा, ईवी सेक्टर अभी भी ₹आत्मनिर्भर₹ बनने से कुछ दूर है। कच्चे माल की आपूर्ति, तकनीक और आयात निर्भरता, विशेष रूप से चीन पर, लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन का ऑटोमोबाइल उद्योग, पर्याप्त सरकारी समर्थन से उत्साहित होकर, ईवी तकनीक में तेजी से आगे बढ़ा है, जिससे यह ईवी और संबंधित घटकों का प्रमुख निर्यातक बन गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण-2024 में सुझाव दिया गया है कि भारत को चीनी निवेश का स्वागत करना चाहिए और देश से आयात कम करना चाहिए, खासकर तब जब अमेरिका और यूरोप चीन से अपना सोर्सिंग हटा रहे हैं। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सभी ऑटोमोटिव निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 29% थी।

इसके अलावा कई बाधाएँ हैं। सियाम के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा कहते हैं, ₹कीमत, विकल्प, ड्राइविंग रेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाधाएँ हैं। पीएम ईड्राइव योजना ने [सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए] धन आवंटित किया है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे मुख्यधारा का विकल्प बनना चाहिए।"

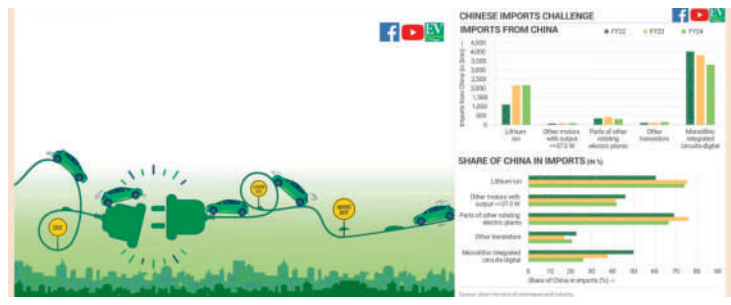

बैटरी और कीमत को लेकर चिंता, खासतौर पर, ग्राहकों की दिलचस्पी को सीमित करती है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ संतोष अय्यर कहते हैं, ₹एक प्रमुख चुनौती ईवी की उच्च प्रारंभिक लागत है, जो उन उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करती है जो अभी भी टिकाऊ गतिशीलता विकल्पों के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती ईवी से जुड़ी मिथक हैं, जैसे कम बैटरी लाइफ और अवशिष्ट मूल्य जोखिम, जो ग्राहकों की भावना को कम करते हैं।"

चीन का वैश्विक एकाधिकार

जीटीआरआई के एक अध्ययन में कहा गया है कि चीन 2023 में वैश्विक ईवी बाजार में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने 36.7 बिलियन डॉलर मूल्य के 1.6 मिलियन ईवी निर्यात किए हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका महत्वपूर्ण खरीदार थे, चीन ने ईयू को 19.5 बिलियन डॉलर मूल्य के ईवी पार्ट्स और अमेरिका को 9.1 बिलियन डॉलर मूल्य के 438,000 ईवी निर्यात किए।

जीटीआरआई के संस्थापक और भारतीय व्यापार सेवा के पूर्व अधिकारी अजय श्रीवास्तव कहते हैं, ₹केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक बैटरी की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर है। चीन बैटरी और मोटर से सुसज्जित चेसिस की आपूर्ति करना चाहता है, जिसकी कीमत ईवी की लागत का 50% से अधिक होती है।"

अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी के उत्पादन में महत्वपूर्ण संसाधन लिथियम भंडार अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में मौजूद हैं। हालाँकि, चीन ने इनमें से अधिकांश क्षेत्रों का दोहन किया है और कई खदानों को पट्टे पर लिया है। ₹तीस साल पहले, नब्बे के दशक की शुरुआत में, चीन ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का दौरा किया और लिथियम, कोबाल्ट और अन्य कीमती धातु [भंडार] को 50-60 साल के लिए लंबी लीज़ पर ले लिया। उन्होंने इन धातुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। कुछ अन्य लोगों के पास भी पहुँच है, लेकिन किसी के पास इस खनिज को संसाधित करने की तकनीक नहीं है। बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातुओं कोबाल्ट, निकल और लिथियम पर चीन का पूर्ण नियंत्रण है।

यह एक बड़ी बाधा है। फरवरी 2023 में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम पाया, लेकिन भंडार के लिए अभी तक कोई सफल बोली नहीं लगी है। श्रीवास्तव कहते हैं, ₹चीन दुनिया की 80% से अधिक [ईवी] बैटरी का उत्पादन करता है। बाकी दुनिया में 20% का उत्पादन होता है, लेकिन यह तुलनात्मक रूप से अधिक महंगा है।"

इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत का 70% हिस्सा चीन द्वारा उत्पादित बैटरी और घटकों का होता है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता काइनेटिक इंजीनियरिंग के प्रबंध निदेशक अजिंक्य फिरोदिया कहते हैं, ₹सबसे बड़ी बाधा सेल का निर्माण करना है, जिसके लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है। इस तरह के बड़े निवेश के लिए भारत के पास एक बड़ा बाजार होना चाहिए। यह मुर्गी और अंडे वाली स्थिति है, जिसे हल करने की आवश्यकता है।"

निषेधात्मक इनपुट लागत

जीटीआरआई की रिपोर्ट कहती है कि भारत की आयात पर भारी निर्भरता, खास तौर पर चीन पर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उच्च इनपुट लागत की व्याख्या करती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उतार-चढ़ाव समस्या को और बढ़ा देता है, क्योंकि चीन वैश्विक बैटरी उत्पादन क्षमता पर हावी है।

ग्रांट थॉर्नटन भारत के ऑटो और ईवी उद्योग के प्रमुख, पार्टनर साकेत मेहरा कहते हैं, "ईरान-इज़राइल संघर्ष जैसे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी औद्योगिक धातु बाज़ारों को प्रभावित किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी एल्युमीनियम, तांबा और निकल पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। नतीजतन, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों से उम्मीद की जा रही है कि वे ज़्यादा रूसी धातुओं को अवशोषित करेंगे, संभवतः कम कीमतों पर, लेकिन इससे इनपुट लागत में वृद्धि हो सकती है।"

जैसे-जैसे इनपुट लागत बढ़ती है, वैसे-वैसे अंतिम कीमत भी बढ़ती है। अक्टूबर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के डेटा से पता चलता है कि साल-दर-साल आधार पर ईवी की बिक्री में लगभग 8% की गिरावट आई है। ईवी की ऊंची कीमतें, चार्जिंग स्टेशनों की कमी और सब्सिडी तक कम पहुंच के कारण खरीदार इन वाहनों को कम आकर्षक बनाते हैं। बिक्री में गिरावट के कारण मुनाफ़े पर असर पड़ता है।

अगस्त 2023 में सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) द्वारा लाई गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कथित ईवी सब्सिडी हेराफेरी घोटाले के बाद सरकार द्वारा 22 महीने तक सब्सिडी रोके रखने से ईवी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को 9,075 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म कियर्नी में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के पार्टनर राहुल मिश्रा कहते हैं, ₹लेकिन मुख्य रूप से, विभिन्न क्षेत्रों में विद्युतीकरण की अपेक्षाकृत धीमी पहुंच और इसलिए ओईएम और टियर-1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा धीमे निवेश के कारण आयात पर कुछ हद तक निर्भरता बढ़ गई है।"

टेकमैटर्स

चीन पर निर्भरता तकनीक तक भी फैली हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि जर्मनी और अमेरिका के पास एक जैसी तकनीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक विकसित करने में चीन सबसे आगे रहा है - और इसके परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण को बनाने वाले घटकों को भी विकसित करने में चीन सबसे आगे रहा है।

वित्तीय परामर्श सेवा फर्म पीडब्ल्यूसी में ऑटोमोटिव क्षेत्र के पार्टनर कवन मुख्तार कहते हैं, ₹चीन ईवी को अपनाने में अग्रणी रहा है और इसके परिणामस्वरूप, चाहे दोपहिया वाहन हों या कार या बसें, चीन में सबसे अधिक उत्पादन और बिक्री होती है और इसलिए आपूर्ति श्रृंखला बहुत अच्छी तरह से स्थापित है।"

क्या भारत पश्चिमी देशों से तकनीक खरीद सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा नहीं है। मुख्तार कहते हैं, "भारत में हमें किफायती कीमतों की जरूरत है। यह यूरोपीय या अमेरिकी कीमतों पर नहीं हो सकता।"

अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ द्वारा चीन निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण, चीन अपने उत्पादन और असेंबली इकाइयों को अन्य देशों में स्थानांतरित कर रहा है, जिसकी शुरुआत आसियान देशों और भारत से हो रही है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया कहते हैं, "देश में मूल्य श्रृंखला को और अधिक लाने के प्रयास के तहत, हम [प्रौद्योगिकी के समग्र आयात में] निवेश पर भी विचार कर रहे हैं।"

उद्योग निकाय एक्मा और सियाम इस बात पर सहमत हुए कि भारत को आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। ऐसा करने का एक तरीका स्थानीयकरण को बढ़ाना है। गिरते रुपये और अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य के संयुक्त दबाव ने भी आयात पर निर्भरता कम करना अनिवार्य बना दिया है। शैलेश चंद्रा कहते हैं, "विदेशी मुद्रा में किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव का असर पड़ता है, लेकिन मैं कहूंगा कि यही कारण है कि सरकार ने पीएलआई योजना शुरू की है। उम्मीद है कि अगले दो से तीन सालों में देश में बड़े पैमाने पर सेल निर्माण शुरू हो जाएगा।"

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति: भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण

विजय गर्ग

के. कस्तूरीरंगन समिति द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की शुरूआत के साथ भारत का शिक्षा परिदृश्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। जुलाई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस ऐतिहासिक नीति का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक सीखने में समावेशिता, गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करते हुए देश की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इस व्यापक गाइड में, हम एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताओं और निहितार्थों पर प्रकाश डालेंगे, और भारत में शिक्षा के भविष्य को आकार देने की इसकी क्षमता की खोज करेंगे। एनईपी कब लागू होगी? एनईपी को 2023-2024 शैक्षणिक वर्ष के दौरान लागू किया जाना शुरू हुआ। इसे भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाएगा। इससे क्या बदलाव आएगा? एनईपी ने विभिन्न बदलाव लाए, जिनमें पाठ्यक्रम में अपडेट, ग्रेड संरचना में संशोधन और भारतीय शैक्षिक प्रणाली के कामकाज में मूलभूत परिवर्तन शामिल हैं। एनईपी का लक्ष्य क्या हासिल करना है? एनईपी का लक्ष्य कई प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ एक समग्र बहु-विषयक शिक्षा बनाना है जो शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देता है।

क्या एनईपी परीक्षाओं को पूरी तरह खत्म कर देता है, या उन्हें नया स्वरूप देता है? जबकि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को कम करने के लिए उन्हें फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। छात्र अपनी रुचि के आधार पर विषयों का चयन कर सकते हैं, और परीक्षा याद रखने के बजाय मुख्य कौशल पर केंद्रित होगी। परीक्षाएं भी आसान होंगी, जिससे सभी छात्र बुनियादी प्रयास से उत्तीर्ण हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता पड़ने पर छात्र सुधार के लिए वर्ष में दो बार परीक्षा दे सकते हैं। अब, आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर करीब से नज़र डालें। यह व्यापक विश्लेषण आपके सभी प्रश्नों का समाधान करेगा और एनईपी में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। एनईपी 2020 की नींवः समावेशी और न्यायसंगत शिक्षाः समावेशी शिक्षा पर एनईपी का ध्यान सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या क्षमताओं के बावजूद, सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना है। एनईपी हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जैसे कि लड़कियों और विकलांग बच्चों, को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर देती है। गुणवत्ता और प्रासंगिकताः 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। एनईपी छात्रों को भविष्य के कार्यबल के लिए व्यावहारिक कौशल से लैस करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा के एकीकरण की वकालत करता है। एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएंः वर्तमान में, 10+2 शैक्षिक संरचना में 3-6 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल नहीं हैं, क्योंकि औपचारिक स्कूली शिक्षा आम तौर पर कक्षा 1 के साथ 6 साल की उम्र में शुरू होती है। हालांकि, नए 5+3+3+4 ढांचे के तहत, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एकीकृत है, जिसका लक्ष्य शुरुआती चरणों से ही उन्नत शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई): एक बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक संचयी विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है, जो स्वस्थ मस्तिष्क के विकास और विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क की उचित देखभाल और उत्तेजना के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। एनईपी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसीई तक सार्वभौमिक पहुंच की कल्पना करता है। यूनिसेफ के अनुसार, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में निवेश से महत्वपूर्ण रिटर्न मिलता हैखर्च किए गए प्रत्येक डॉलर के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक लाभ में $17 तक का रिटर्न मिलता है।

मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकताः पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ बुनियादी संचालन करने की क्षमता, सभी भविष्य की स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए एक आवश्यक आधार और एक अनिवार्य शर्त है। पूरे प्रारंभिक और मिडिल स्कूल पाठ्यक्रम में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर और आम तौर पर पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनती, अंकगणित और गणितीय सोच पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यूनेस्को के अनुसार, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल-आयु आबादी है, जो मजबूत शैक्षिक सुधारों के महत्व पर प्रकाश डालता है। स्कूली शिक्षाः एनईपी ग्रेड 6 से समग्र विकास, बहु-विषयक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की वकालत करता है। उच्च शिक्षाः एचईआई के लिए एकल नियामक निकाय, लचीले पाठ्यक्रम और अनुसंधान और नवाचार पर जोर सहित सुधारों का प्रस्ताव है। त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषी सीखने की प्रक्रिया शोध से पता चलता है कि बच्चे 2 से 8 साल की उम्र के बीच तेजी से भाषाएँ सीखते हैं, और कई भाषाएँ बोलने में सक्षम होने से युवा छात्रों के लिए कई संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। त्रि-भाषा योजना का उपयोग अभी भी किया जाएगा। यदि छात्र सीखी जा रही तीन भाषाओं में से एक या अधिक भाषाएँ बदलना चाहते हैं, तो वे ग्रेड 6 या 7 में ऐसा कर सकते हैं। उन्हें बस यह दिखाना होगा कि वे बुनियादी स्तर पर तीन भाषाएँ बोल सकते हैं। पोषण कौशलः यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र महत्वपूर्ण कौशल सीखें, एनईपी पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़ता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग और व्यावसायिक कौशल जैसे आधुनिक विषयों को जोड़ना शामिल है। डिजिटल कौशल जैसे कोडिंग और कंप्यूटर को समझना। पर्यावरण शिक्षा भी शामिल होगी। आकलन और मूल्यांकनः योग्यता-आधारित मूल्यांकनः समग्र सीखने के परिणामों को मापने के लिए रटने की बजाय योग्यता-आधारित मूल्यांकन की ओर बदलाव। एनईपी वार्षिक रिपोर्ट कार्ड से समग्र प्रगति कार्ड में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है रचनात्मक मूल्यांकन प्रथाएँः समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने और छात्रों के सीखने में सहायता करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। सहकर्मी मूल्यांकन, स्व-मूल्यांकन और फीडबैक-उन्मुख मूल्यांकन छात्रों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

छात्रों की अद्वितीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करनाः प्रत्येक छात्र में अद्वितीय प्रतिभाएँ होती हैं जिन्हें खोजने और निखारने की आवश्यकता होती है। यदि कोई छात्र किसी निश्चित क्षेत्र में असाधारण योग्यता दिखाता है, तो उसे आगे खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक उन विषयों में अतिरिक्त सामग्री और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे जिनके प्रति छात्र भावुक हैं। इसमें विज्ञान या गणित मंडल, संगीत और नृत्य प्रदर्शन, शतरंज, कविता, भाषाएँ, नाटक, वाद-विवाद, खेल, या इको और योग क्लब जैसी गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। शिक्षक-छात्र अनुपातः वर्तमान शिक्षक-छात्र अनुपातः यूनेस्को के अनुसार, भारत में शिक्षक-छात्र अनुपात लगभग 1:32 है, जो अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता को उजागर करता है। आदर्श शिक्षक-छात्र अनुपातः एनईपी का लक्ष्य व्यक्तिगत ध्यान और प्रभावी सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात को 1:25 तक कम करना है। शिक्षक सशक्तिकरणः शिक्षकों को अपने कौशल और शैक्षणिक प्रथाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (निष्ठा) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को शैक्षणिक तकनीकों और नवीन शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित करना है। स्कूल संरचना और द्रव प्रवेशय योजनाः द्रव विद्यालय प्रवेश योजनाः एनईपी एक लचीली स्कूल प्रवेश और निकास योजना का प्रस्ताव करता है, जिससे छात्रों को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर विभिन्न चरणों में प्रवेश और निकास की अनुमति मिलती है।
बहुविषयक शिक्षाः स्कूल बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे छात्रों को कला, विज्ञान, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और खेल में विषय चुनने की अनुमति मिलेगी।
ड्रॉपआउट रोकथाम पर एनईपी का फोकसः स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि बच्चों का नामांकन हो और स्कूल जा रहे हैं. ग्रेड 6-8 के लिए जीईआर-सकल नामांकन अनुपात 90.9% था, जबकि ग्रेड 9-10 और 11-12 के लिए यह क्रमशः 79.3% और 56.5% था - यह दर्शाता है कि नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात ग्रेड 5 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। और विशेषकर कक्षा 8 के बाद। 2030 तक प्रीस्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने के लक्ष्य के साथ, इन बच्चों को जल्द से जल्द शैक्षिक दायरे में वापस लाना और आगे के छात्रों को पढ़ाई छोड़ने से रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। समग्र साक्षरता दरः भारत की साक्षरता दरः भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की समग्र साक्षरता दर 74.04% है, जो हाल के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। साक्षरता पर एनईपी का प्रभावः एनईपी का लक्ष्य नवीन शिक्षण विधियों, समावेशी शिक्षा प्रथाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है। प्रौद्योगिकी की भूमिकाः डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरः ऑनलाइन शिक्षण और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच का समर्थन करने के लिए मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सभवमन प्लेटफॉर्म विभिन्न संस्थानों से मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो देश भर के शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार होगा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर उपलब्ध कराया गया। कस्तूरीरंगन समिति और उसकी सिफारिशें: कस्तूरीरंगन समितिः एनईपी कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों से प्रभावित थी, जिसने शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा था। सिफ़ारिशें लागू की गईंः कस्तूरीरंगन समिति की कई सिफारिशें, जैसे स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर, को एनईपी में शामिल किया गया है। एनईपी 2020 पिछली नीतियों से कैसे अलग है? पिछली शिक्षा नीतियां मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित थीं कि हर किसी की शिक्षा तक पहुंच हो। नई नीति उन लक्ष्यों को संबोधित करती है जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरी तरह से हासिल नहीं किए गए थे, जिसे 1992 में अद्यतन किया गया था। तब से एक महत्वपूर्ण बदलाव बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसने सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना एक कानूनी आवश्यकता बना दिया है। निष्कर्षः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शैक्षिक सुधार के एक नए युग की शुरुआत करती है, जो एक समग्र, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के लिए मंच तैयार करती है। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, एनईपी शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को साकार करने और भारत के शिक्षार्थियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की आशा प्रदान करता है।

संपादक की कलम से

जैविक खाद्य विकल्पों के लाभ और वास्तविकता

जैविक भोजन विकल्प

ताज़ी काटी गई फसलों से लेकर पैक किए गए खाद्य पदार्थों तक, जैविक लेबल अब प्रीमियम मूल्य का आदेश देता है; क्या यह वास्तविक है या सिर्फ बिक्री का हथकंडा है

हाल के वर्षों में, एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति उभरी है, जैविक उत्पाद अब सुपरमार्केट अलमारियों पर प्रमुखता से प्रदर्शित होते हैं और बोर्ड भर में पैकेजिंग पर प्रदर्शित होते हैं। इसमें ताज़ी कटी हुई फसलों से लेकर आवश्यक पैक किए गए सामान तक सब कुछ शामिल है। और, यह देखते हुए कि जैविक ब्रांड की लागत काफी अधिक होगी, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यह इसके लायक है।

जैविक खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य, रोगविज्ञान और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं। इस प्रकार के भोजन को अधिक पौष्टिक और सात्विक विकल्प के रूप में प्रचारित किया जाता है। अवधारणा सीधी हैः कीटनाशकों का उपयोग कम करें, सिंथेटिक उर्वरकों को खत्म करें, और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से बचें। कई व्यक्तियों के लिए, स्वच्छ और अधिक जैविक रूप से खेती की गई उपज का चयन करना खर्च को उचित ठहराता है। और फिर भी, क्या हम, अपने तरीके से, ग्राहक के रूप में हमारे वास्तविक मूल्य से वंचित नहीं हो रहे हैं?

वर्षों पहले, औद्योगिक खेती के उदय से पहले, भिंडी जैसी सब्जियों का अनुमान बहुत कम था। हमें अक्सर अंदर कीड़े मिलते हैं, जो उस वातावरण का एक अप्रिय लेकिन स्वाभाविक अनुस्मारक है जिसमें वे बड़े हुए थे। इन ₹खामियोंर ने हमें आश्वस्त किया कि उत्पाद प्रामाणिक था, सिंथेटिक रसायनों से अछूता था। आज तक तेजी से आगे बढ़ा, और उत्पादन चित्र-परिपूर्ण है, लेकिन व्यापार-बंद महत्वपूर्ण रहा है।

हमारी सब्जियाँ, जो कभी जीवंत और स्वाद से भरपूर थीं, अब कीटनाशकों में लिपटी हुई हैं जो उनका प्राकृतिक सार छीन लेती हैं। हम सभी ने इस पर ध्यान दिया हैः टमाटरों का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा और शिमला मिर्च का स्वाद भी फीका है। हमारे अनुभव से ताजी सब्जियों का सार लुप्त हो रहा है, कई लोगों ने पहले से पैक किए गए भोजन की सुविधा का सहारा लिया।

फास्ट फूड या पैकेज्ड स्नैक्स का आकर्षण और स्वाद उनके साथ पेश की जाने वाली सब्जियों की उपस्थिति पर हावी हो जाता है।

यह शायद ही अप्रत्याशित है कि बहुत से लोग खुद को कम आकर्षक, समय लेने वाले सुपरफूड और जल्दी, अधिक स्वादिष्ट भोजन विकल्पों के बीच फंसा हुआ पाते हैं। फिर भी, भुगतान करने की कीमत क्या है? यहाँ मुद्दा यह हैः यह स्वाद या सहजता के बारे में नहीं है - यह भलाई के बारे में है।

यहां तक कि कीटनाशकों के न्यूनतम संपर्क को भी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है, जिनमें हार्मोन व्यवधान और तंत्रिका संबंधी जटिलताएं शामिल हैं। जैसे-जैसे समय बीतता है, ये पदार्थ मानव शरीर के भीतर जमा हो सकते हैं, और लगातार कड़े नियमों के बावजूद, दीर्घकालिक परिणाम काफी हद तक अस्पष्ट रहते हैं।

यह जैविक खाद्य पदार्थों के मूल्य को सुदृढ़ करते हुए, उच्च मूल्य टैग को उचित ठहराता है। क्या ₹जैविक₹ हमेशा बेहतर गुणवत्ता का पर्याय है? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक पूर्णता की गारंटी नहीं देता। प्रमाणन प्रक्रियाओं में अंतराल है, जिसका अर्थ है कि कीटनाशक-मुक्त होना आवश्यक रूप से ₹जैविक₹ के बराबर नहीं है। यह सिंथेटिक रसायनों में कमी और अधिक टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने का वादा करता है। इसके अतिरिक्त, जैविक खेती जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती है - दोनों हमारे ग्रह के भविष्य के लिए आवश्यक हैं। क्या यह एक सार्थक निवेश है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को सबसे अधिक महत्व देते हैं। रासायनिक जोखिम को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में जैविक का चयन एक सकारात्मक कदम है। हालाँकि, वास्तव में अपने भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए, स्थानीय किसानों और ताज़ा उपज की तलाश करना, जो अत्यधिक प्रसंस्करण या लंबी दूरी के परिवहन से नहीं गुजरा है, उस मुद्दे का अधिक प्रभावी समाधान हो सकता है।

जैविक विकल्पों को अपनाना महज वित्तीय विचारों से परे है; यह आपकी भलाई के प्रति प्रतिबद्धता, आपके पाक अनुभव में वृद्धि और हमारे खाद्य प्रणालियों के भविष्य के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

राय

डिजिटल माध्यमों का बढ़ता दुष्प्रभाव

डिजिटल क्रांति के वर्तमान दौर में डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने मानव जीवन को बेहद सुविधाजनक और आसान बना दिया है, परंतु इनके अंधाधुंध उपयोग ने इंसान के समक्ष समस्याओं का अंबार खड़ा कर दिया है। वस्तुतः स्मार्टफोन का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। जिसने स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा की हैं।

बीते दिनों हुए अध्ययन समाज विज्ञानियों की चिंता के जीते-जागते सबूत हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों द्वारा किया गया एक हालिया अध्ययन जो 'जर्नल आफ जनरल इंटरनल मेडिसीन' में प्रकाशित हुआ है, उसमें विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि कम उम्र या 20 साल की आयु तक ज्यादा स्मार्टफोन या टीवी देखने से दिल कमजोर हो जाता और दिल का दौरा पड़ने के खतरे की आशंका काफी बढ़ जाती है। अधिक समय तक स्क्रीन देखने से नींद और शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के किंग्स कालेज और लंदन के मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के विज्ञानियों के शोध अध्ययन के अनुसार, हर पांच में से एक किशोर में अधिक समय तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।

पर्यावरण पर हो रहे दुष्प्रभाव के बारे में इंग्लैंड के लाफबोरो यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों के अध्ययन के प्रमुख प्रोफेसर आयान हाकिंसन का मानना है कि डिजिटल डाटा का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सही है कि डिजिटल माध्यम से भेजी जाने वाली एक तस्वीर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन यदि आप अपने फोन में मौजूद सभी तस्वीरों, मीम्स आदि को देखते हैं तो इससे ऊर्जा खपत में वृद्धि होती है। क्लाउड आपरेटर आपसे जंक डाटा डिलीट करने को कहते हैं, क्योंकि जितना डाटा संग्रहित किया जाता है, उतने ही ज्यादा लोग उनके सिस्टम का उपयोग करने के लिए भुगतान करते हैं। यहां यह जान लेना जरूरी है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन से जलवायु का संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। तेल, गैस और कोयला से तो यह हो ही रहा है, जंक डाटा भी उसमें से एक है जो इसका एक अहम कारक बनता जा रहा है। आने वाले समय में यह संकट और बढ़ेगा।

जंक डाटा से निपटना जलवायु संकट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वस्तुतः गूगल, माइक्रोसाफ्ट्स जैसी इंटरनेट आधारित कंपनियों के बड़े-बड़े डाटा सेंटर हजारों की संख्या में सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी मात्रा ऊर्जा की खपत करते हैं जिससे वातावरण में गर्मी पैदा होती है। उसे नियंत्रित करने के लिए बड़े- बड़े एयरकंडीशनर उपयोग में लाए जाते हैं जो डाटा सेंटर को तो ठंडा रखते हैं, लेकिन बाहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है।

भारत-चीन : 'छलावा शांति' का कोहरा

मनीष तिवारी

रूस के ककाान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई बैठक को संभावित गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) पर अप्रैल-मई 2020 के चीनी अतिक्रमण...

रूस के ककाान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई बैठक को संभावित गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) पर अप्रैल-मई 2020 के चीनी अतिक्रमण और कुछ अन्य निकट अवधि के विरासती मुद्दों को संबोधित करने के लिए जून, 2020 से चल रही लंबी बातचीत को पूरा किया। जबकि मोदी और शी दोनों ने एल.ए.सी. पर शांति बहाल करने और शांति बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। दोनों देशों द्वारा जारी बैठक के आधिकारिक रीडआऊट में विसंगतियों ने एल.ए.सी. पर स्थिति की उनकी संबंधित सराहना में विसंगतियों, मतभेदों और द्वंद्वों को उजागर किया।

भारत का दावा है कि वास्तविक सीमा 3,488 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि चीन का कहना है कि यह काफी कम है। पेइचिंग अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि नई दिल्ली का कहना है कि अक्साई चिन में 38,000 वर्ग किलोमीटर लद्दाख का हिस्सा है। देपसांग और डेमचोक में विघटन (डिसइंगेजमैंट) प्रयासों पर काफी ध्यान देने के बावजूद ऐसे कई अनसुलझे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं।

2020 के सीमा विवाद से पहले की स्थिति : भारत सरकार ने 2020 में तनाव बढऩे से पहले चीनी घुसपैठ की प्रकृति या सीमा या लद्दाख में भारतीय गश्ती दल के सामने आने वाली कठिनाइयों का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया। इस अस्पष्टता ने विघटन की सटीक शर्तों के बारे में अटकलों को हवा दी है। वर्तमान सीमा विवाद का मुख्य कारण भारत और चीन के बीच सीमाओं के संबंध में चीन के दावों में निहित है। इस संबंध में चीनी विवाद को पहली बार प्रीमियर झोऊ एनलाई ने 7 नवंबर, 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू को लिखे एक पत्र में व्यक्त किया था और अब इसे बोलचाल की भाषा में चीनी 1959 दावा रेखा के रूप में जाना जाता है। तब से एल.ए.सी. के साथ लगे कई क्षेत्र विवादास्पद बने हुए हैं।

अप्रैल-मई 2020 से पहले देपसांग मैदानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तनाव पहले से ही प्रकट हो रहा था, जहां चीनी सैनिक अक्सर कई बिंदुओं, जैसे कि पैट्रोलिंग प्वाइंट 10, 11, 11-ए, 12 और 13 पर भारतीय गश्ती दल को बाधित करते थे। हालांकि भारत ने पश्चिम में बर्टसे क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन सितंबर 2015 में एक महत्वपूर्ण गतिरोध के बाद से यह हमेशा एक फ्लैशप्वाइंट रहा है, जब भारत ने एक चीनी वॉचटावर के निर्माण पर आपत्ति जताई थी। जून 2020 में हिंसक टकराव से पहले गलवान घाटी में भी घर्षण का अनुभव हुआ था। गश्ती सीमाओं की आपसी समझ ने ऐतिहासिक रूप से शांति बनाए रखने में मदद की है।

2020 का अतिक्रमण एक महत्वपूर्ण मोड़ : अप्रैल-मई 2020 में चीनी अतिक्रमण ने सीमा विवाद में महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया, जिसने एल.ए.सी. पर गतिशीलता को मौलिक रूप से बदल दिया। इस अवधि के दौरान, चीनी सैनिक भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में गहराई तक आगे बढ़े, जिससे क्षेत्र में नए टकराव के बिंदू बन गए। गलवान घाटी में हिंसक टकराव, जिसके परिणामस्वरूप 20 भारतीय सैनिक मारे गए, ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया। चीनी सेना ने उन क्षेत्रों में शिविर स्थापित किए, जहां पहले संयुक्त रूप से गश्त की जाती थी, जिससे पहले से मौजूद नाजुक समझौतों को कमजोर किया गया।

पैंगोंग त्सो विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जिसमें चीनी सैनिक उत्तरी तट पर आगे बढ़े और फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच की स्थिति पर कब्जा कर लिया। इस आक्रामक युद्धाभ्यास ने सीमा को पश्चिम की ओर धकेल दिया और लंबे समय के गतिरोध की शुरुआत की। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्रों में भी इसी तरह की घुसपैठ देखी गई, जिससे विघटन के लिए बातचीत जटिल हो गई। देपसांग मैदानों में चीनी सेना ने भारतीय गश्तों में बाधा डालना जारी रखा और इस क्षेत्र से पीछे हटने में चीन की अनिच्छा अभी भी चिंता पैदा करती है कि 2020 से पहले की स्थिति में पूरी तरह से वापसी उतनी आसानी से संभव नहीं हो सकती, जितना कि सरकार द्वारा दिखावा किया जा रहा है।

बफर जोन और गश्त प्रतिबंध - एक नई वास्तविकता : 2020 में तनाव बढऩे से एल.ए.सी. पर बफर जोन की स्थापना हुई, जहां भारतीय और चीनी दोनों सेनाओं को गश्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि इस उपाय से तात्कालिक तनाव कम हो सकता है, लेकिन इसने भारत की उन क्षेत्रों तक पहुंच को भी प्रतिबंधित कर दिया, जहां पहले स्वतंत्र रूप से गश्त की जाती थी। इस व्यवस्था ने टकराव की संभावना को तो कम कर दिया है लेकिन भारत के दीर्घकालिक क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या चीन ने 2020 के गतिरोध के दौरान अपने कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से पूरी तरह से वापसी कर ली है।

जनवरी 2023 में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे गए एक पेपर में विस्तृत रूप से बताया गया है कि भारतीय सुरक्षा बल नियमित रूप से काराकोरम दर्रे से चुमुर तक 65 गश्ती बिंदुओं (पी.पी.) पर गश्त करते हैं। हालांकि, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा गश्त के निलंबन के कारण इनमें से 26 पी.पी. तक पहुंच खो गई है। विशेष रूप से, बिना गश्त वाले पीपी में दौलत बेग ओल्डी के उत्तर-पूर्व में समर लुंगपा क्षेत्र और देपसांग मैदानों के साथ-साथ पैंगोंग के उत्तरी तट और डेमचोक और चाृडग नाला जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं।

अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता : भारत-चीन सीमा पर चल रही विघटन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए, जहां चीन भारतीय क्षेत्र पर दावा करता है। इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि ये विघटन समझौते और संकल्प अक्साई चिन पर भारत के दावों को कमजोर करेंगे, जिसका वर्तमान सरकार ने 6 अगस्त, 2019 को लोकसभा में अनुच्छेद 370 पर बहस के दौरान आक्रामक तरीके से समर्थन किया था। हालांकि हाल के समझौतों को ठोस प्रगति कहा जा सकता है, लेकिन इसकी शर्तों के संबंध में पारदूशता महत्वपूर्ण है।

राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों में वृद्धि

राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक सुरक्षा निस्संदेह आवश्यक है। आॢथक स्थिरता, मानव पूंजी विकास, कार्यबल की बढ़ती भागीदारी और आर्थिक नीतियों के समर्थन जैसे कई प्रमुख कारणों से, विशेष रूप से श्रमिकों के संबंध में, इसकी विशेष आवश्यकता है।

राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक सुरक्षा निस्संदेह आवश्यक है। आॢथक स्थिरता, मानव पूंजी विकास, कार्यबल की बढ़ती भागीदारी और आॢथक नीतियों के समर्थन जैसे कई प्रमुख कारणों से, विशेष रूप से श्रमिकों के संबंध में, इसकी विशेष आवश्यकता है। बेरोजगारी, बीमारी या सेवानिवृत्ति जैसी आकस्मिकता के दौरान श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा उपभोक्ता खर्च को बनाए रखने, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। एक विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था लोगों को श्रम बाजार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे राष्ट्र के सततविकास के उद्देश्य से व्यापक आॢथक नीतियों को मदद मिलती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करने; प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पी.एम.-एस.वाई.एम.) और राष्ट्रीय पैंशन योजना-व्यापारी योजना जैसे कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और उपाय कार्यान्वित किए हैं।

इनमें श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने और अनुपालन की जटिलता को कम करने के लिए एकीकृत वैब पोर्टल 'श्रम सुविधा पोर्टल' का शुभारंभ, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि पर जानकारी जैसी विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा में बदलाव के लिए एन.ई.एस. की शुरुआत; असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल का विकास, जो रोजगार की मनोनुकूल प्राप्ति के लिए आधार के साथ जुड़ा हुआ है और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार करता है; कोविड-19 के कारण मौत के मामले में बीमित लोगों (आई.पी.) के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए ई.एस.आई.सी. कोविड-19 योजना; मातृत्व लाभ की मात्रा में वृद्धि, ई.एस.आई.सी. योगदान की दर में कमी इत्यादि शामिल हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत सामाजिक सुरक्षा संगठन- कर्मचारी राज्य बीमा निगम हमारे देश के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। चिकित्सा और नकद लाभ जैसी इसकी विभिन्न लाभ योजनाओं के माध्यम से हमारे देश के श्रमिकों को पिछले 7 दशकों से फायदा हो रहा है। हमारे श्रमयोगी परिवारों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की देखभाल करने वाले ई.एस.आई.सी. ने पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति की है। इस अवधि के दौरान ई.एस.आई.सी. ने अपनी सेवाओं का विस्तार 393 जिलों से 674 जिलों तक कर लिया है। इससे आज स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ 3.72 करोड़ कामकाजी परिवारों तक पहुंच रहा है, जो वर्ष 2014 में 1.95 करोड़ तक सीमित था। कुल लाभार्थी 2014 में 7.58 करोड़ से बढ़कर 2024 में 14.43 करोड़ हो गए हैं।

हमारे देश के कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को समग्र रूप से मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। उन्होंने 29 अक्तूबर, 2024 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ए.आई.आई.ए.), नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत ई.एस.आई.सी. में12,855 करोड़ रुपए के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत की।

इन परियोजनाओं के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 300 बिस्तरों वाले ई.एस.आई.सी. अस्पताल का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया, जिसे भविष्य में 500 बिस्तरों तक विस्तारित किया जा सकता है। इस सुविधा से लगभग 14 लाख बीमित लोगों और उनके परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा, उन्होंने 1,030 बिस्तरों की संयुक्त क्षमता वाली 6 ई.एस.आई. अस्पताल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं के लिए कुल निवेश राशि 1,641 करोड़ रुपए है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) अस्पतालों का उद्घाटन और शिलान्यास भारत में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए अस्पतालों की स्थापना के जरिए मोदी सरकार का लक्ष्य विशेष रूप से औद्योगिक और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। ये अस्पताल बाह्य रोगी देखभाल, आंतरिक रोगी सेवाएं, आपातकालीन देखभाल और विशेष उपचार सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगे।

गुणवत्ता पर सरकार का यह ध्यान सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को समय पर और प्रभावी चिकित्सा ध्यान मिलेगा, जो स्वस्थ कार्यबल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनमोल कार्यबल और उनके परिवारों की मदद करके राष्ट्र निर्माण में अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। ई.एस.आई.सी. अस्पतालों की स्थापना को प्राथमिकता देकर मोदी सरकार कार्यबल की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर रही है, जो श्रमिक कल्याण और राष्ट्र के समग्र आॢथक स्वास्थ्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना कितना सुरक्षित? यहां जाने हर डिटेल्स

परिवहन विशेष न्यूज

हाइब्रिड म्युचुअल फंड भी निवेश का काफी अच्छा ऑप्शन है। यह म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है। इसमें निवेश करने पर बेहतर रिटर्न भी मिलता है साथ ही इसमें रिस्क भी कम है। अगर आप भी निवेश के लिए ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आपको एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। आइए जानते हैं कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना कितना सुरक्षित है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड काफी सही माना जा रहा है। शानदार रिटर्न के लिए यह निवेशकों के बीच पॉपुलर हो गया है, लेकिन रिस्क को देखते हुए कई लोग इसमें पैसे लगाने से डरते हैं। दरअसल, म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलता है वह शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड (Hybrid Mutual Fund) के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इस आर्टिकल में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से बताएंगे।

क्या होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड?

म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं जैसे- डेट, इक्विटी और हाइब्रिड। इनमें से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेशक सभी एसेट (जैसे- इक्विटी, डेट, सोने आदि) में निवेश कर सकता है। इस फंड में बाकी दोनों फंड की तुलना में रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है।

अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क कम क्यों है? इसका जवाब है कि इसमें आप सब एसेट में निवेश कर सकते हैं। अगर शेयर बाजार में गिरावट आती है तो गोल्ड और डेट से आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है। माना जाता है कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड में एक साथ गिरावट नहीं आती है। इजरायल और ईरान के मध्य तल रहे तनाव के समय जहां एक तरफ बाजार में गिरावट आई थी तो वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी।

यह भी पढ़ें: Petrol-Diesel Price: नोएडा-गुरुग्राम से सस्ता है राजधानी में फ्यूल,फटाफट चेक करें अपने शहर के ताजा दाम

हाइब्रिड फंड में किसे करना चाहिए निवेश?

अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते साथ ही म्यूचुअल फंड में हो रही ट्रेडिंग के लिए नौसिखिए हैं तो आपको अपने निवेश की शुरुआत हाइब्रिड फंड से करनी चाहिए। अगर आप इसकी जगह इक्विटी में निवेश करते हैं तो संभावना है कि बाजार की जानकारी न होने की वजह से आपको नुकसान हो। वहीं, दूसरी तरफ हाइब्रिड फंड में आपकी पूंजी भी एक हद तक सिक्योर रहेगी और आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा।

अक्सर देखा जाता है कि जो नए निवेशक होते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं होती है और वह गलत तरीके से निवेश करते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नए निवेशकों के लिए हाइब्रिड फंड काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेश करके वह अच्छा रिटर्न के साथ निवेश राशि को सुरक्षित भी रख सकते हैं। बता दें कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड 6 तरह के होते हैं। इसमें कैपेसिटी के हिसाब से इक्विटी, डेट और सोने में इन्वेस्टमेंट का रेश्यो घटता-बढ़ता रहता है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को केंद्र ने दी वित्तीय मदद, जानें किन संकटों से घिरी है ये सरकारी कंपनी

परिवहन विशेष न्यूज

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की स्टील उत्पादन कंपनी है। इसके पास आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 75 लाख टन का प्लांट है। हालांकि, बीते कुछ वर्षों से यह कंपनी कई वित्तीय और परिचालन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINIL) को 1650 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी है। एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, परिचालन और आर्थिक संकट से जूझ रही इस सरकारी कंपनी पर कर्ज लगातार बढ़ा है। ऐसे में संकट को खत्म करने के लिए अब केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने कदम बढ़ाया है।

मंत्रालय ने कहा कि वह आरआईएनएल को चलाने के लिए कई कदम उठा रहा है। सरकार ने बताया कि उसने 19 सितंबर 2024 को इक्विटी के तौर पर आरआईएनआईएल में 500 करोड़ रुपये की मदद दी है। वहीं 27 सितंबर 2024 को उसने वर्किंग कैपिटल लोन को तौर पर उसे 1140 करोड़ रुपये दिए हैं।

सरकार के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के मालिकाना हक वाली एसबीआईकैप्स (SBICAPS) से आरआईएनएल की वहनीयता को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। इस दस्तावेज में इसका भी जिक्र किया गया है कि आरआईएनएल गंभीर वित्तीय संकट में है और इस्पात मंत्रालय इस चिंता के निपटारे के लिए वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहा है।

क्या है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड?

गौरतलब है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की स्टील उत्पादन कंपनी है। इसके पास आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 75 लाख टन का प्लांट है। हालांकि, बीते कुछ वर्षों से यह कंपनी कई वित्तीय और परिचालन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है।

इसके तीन में से दो ब्लास्ट फर्नेस (भट्टियों) को पहले अक्तूबर 2028 तक के लिए बंद कर दिया गया था। इसके चलते आरआईएनएल पर कर्ज 35 हजार करोड़ तक बढ़ गया है।

कंपनी के निजीकरण को मिल चुकी है सैद्धांतिक मंजूरी

इससे पहले जनवरी, 2021 में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी (सीसीईए) ने रणनीतिक विनिवेश के जरिए आरआईएनएल में सरकारी हिस्सेदारी के 100 प्रतिशत विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि, कंपनी के निजीकरण के सरकार के फैसले का श्रमिक संघों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि आरआईएनएल के पास खुद के इस्तेमाल वाली लौह अयस्क खानें नहीं है। इसके चलते उसे मौजूदा संकट झेलना पड़ रहा है।

नोएडा-गुरुग्राम से सस्ता है राजधानी में फ्यूल,फटाफट चेक करें अपने शहर के ताजा दाम

देश की मुख्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोजाना सुबह महानगरों समेत बाकी शहरों के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट करते हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि गाड़ीचालक को हमेशा लेटेस्ट प्राइस चेक करने के बाद ही टंकी फुल करवानी चाहिए। आइए जानते हैं कि 3 नवंबर 2024 को आपके शहर में पेट्रोल-डीजल किस भाव पर बिक रहा है।

नई दिल्ली। भारत में रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Price) अपडेट होते हैं। ऐसे में किसी भी दिन इनकी कीमतों में बदलाव हो सकता है। फिलहाल तो मार्च 2024 से इनके दाम स्थिर बने हुए हैं।

जी हां, आखिरी बार मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2 रुपये की कटौती की गई थी। इसके बाद भी कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव हुए। चूंकि, देश के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अलग बने हुए हैं। इस वजह से गाड़ीचालक को लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही टंकी फुल करवाना चाहिए।

आज के लेटेस्ट रेट (Petrol-Diesel Latest Price)

HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price 3 November 2024)

मेट्रोसिटी में पेट्रोल-डीजल के दाम

- दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.81 रुपये और डीजल की कीमत 87.71 रुपये प्रति लीटर है।
- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.43 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.95 रुपये प्रति लीटर है।
- कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.75 रुपये प्रति लीटर है।
- चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.38 रुपये प्रति लीटर है।

नोएडा समेत शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

- नोएडा: पेट्रोल 94.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.00 रुपये प्रति लीटर
- गुरुग्राम: पेट्रोल 95.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.09 रुपये प्रति लीटर
- बेंगलुरु: पेट्रोल 102.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.98 रुपये प्रति लीटर
- चंडीगढ़: पेट्रोल 94.28 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.44 रुपये प्रति लीटर
- हैदराबाद: पेट्रोल 107.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.69 रुपये प्रति लीटर
- जयपुर: पेट्रोल 104.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.21 रुपये प्रति लीटर
- पटना: पेट्रोल 105.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.09 रुपये प्रति लीटर

क्यों अलग हैं हर शहर में दाम

देश के महानगरों समेत बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अलग हैं। इसकी वजह है कि वर्तमान में पेट्रोल-डीजल जीएसटी (Goods & Service Tax-GST) के दायरे में नहीं आते हैं। इस पर जीएसटी की जगह वैट (Value Added Tax-VAT) लगाया जाता है। चूंकि, वैट की दरें सभी राज्यों में अलग होती है। बता दें कि वैट की दरें राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। यही कारण है कि सभी शहरों में तेल की कमत अलग होती है।

स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद 6 कंपनियों का चढ़ गया एम-कैप, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक रहा टॉप गेनर

परिवहन विशेष न्यूज

Share Market Update शेयर बाजार में पिछले हफ्ते उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहा। इस हफ्ते बाजार के टॉप-10 कंपनियों में से 6 कंपनियों के एम-कैप में बढ़त हुई तो 4 कंपनियों के एम-कैप में गिरावट आई। 1 नवंबर 2024 को शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) हुई थी। इस एक घंटे की स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ।

नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market) का पिछला हफ्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा। बाजार में जारी उतार-चढ़ाव का असर कंपनियों के एम-कैप पर पड़ा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार बाजार की टॉप-10 कंपनियों में से 6 फर्म का संयुक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Capitalisation-MCap) 1,07,366.05 करोड़ रुपये रहा। इस हफ्ते एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के एम-कैप में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली।

1 नवंबर 2024 को दीवाली (Diwali 2024) के मौके पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में एक घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) हुआ था। इस एक घंटे की स्पेशल ट्रेडिंग (Special Trading Session) में शेयर बाजार ने बढ़त के साथ कारोबार रहा।

इन कंपनियों के एम-कैप में आई तेजी

- भारतीय स्टेट बैंक का बाजार मूल्यांकन 36,100.09 करोड़ रुपये बढ़कर 7,32,755.93 करोड़ रुपये हो गया।
- आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,775.58 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,10,686.85 करोड़ रुपये हो गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का एम-कैप 16,887.74 करोड़ रुपये बढ़कर 5,88,509.41 करोड़ रुपये हो गया।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 15,393.45 करोड़ रुपये बढ़कर 18,12,120.05 करोड़ रुपये हो गया।
- आईटीसी के एम-कैप में 10,671.63 करोड़ रुपये जोड़े, जिसके बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 6,13,662.96 करोड़ रुपये हो गया।
- हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार मूल्यांकन (एम-कैप) 2,537.56 करोड़ रुपये बढ़कर 5,96,408.50 करोड़ रुपये हो गया।

इन कंपनियों के एम-कैप में गिरावट

पिछले हफ्ते शेयर बाजार की चार कंपनियों के एम-कैप में गिरावट आई। इन कंपनियों के शेयर ने पिछले पांच सत्रों में नेगेटिव रिटर्न दिया है।

- इन्फोसिस का एमकैप 38,054.43 करोड़ रुपये घटकर 7,31,442.18 करोड़ रुपये रह गया।
- भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 27,299.54 करोड़ रुपये घटकर 9,20,299.35 करोड़ रुपये रह गया।
- टीसीएस का मूल्यांकन 26,231.13 करोड़ रुपये घटकर 14,41,952.60 करोड़ रुपये हो गया।
- एचडीएफसी बैंक का एमकैप 3,662.78 करोड़ रुपये घटकर 13,26,076.65 करोड़ रुपये रह गया।

टॉप-10 फर्म की रैंकिंग

इस हफ्ते भी रिलायंस इंडस्ट्रीस सबसे मूल्यवान कंपनी रही। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी रहे।

कहीं रुक न जाए आपकी पेंशन! 30 नवंबर तक जरूर निपटाएं ये काम

परिवहन विशेष न्यूज

अगर आप भी पेंशन का लाभ उठाते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। नवंबर महीने के अंत तक सभी पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होता है। अगर वह यह काम नहीं निपटाते हैं तो दिसंबर के महीने से उनकी पेंशन रूक सकती है। हम इस आर्टिकल में बताएंगे कि पेंशनर्स किन तरीकों से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

नई दिल्ली। नवंबर का महीना सभी पेंशनर्स के लिए काफी जरूरी रहता है। अगर आप भी पेंशन का लाभ उठाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। नवंबर के अंत तक में केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो दिसंबर से उनकी पेंशन रुक भी सकती है।

लाइफ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी

पेंशनर्स को पेंशन का लाभ पाने के लिए हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Praman Patra) जमा करना होता है। यह लाइफ सर्टिफिकेट प्रूफ होता है कि पेंशनर्स जिंदा है और उसे ही पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

कब जमा करना है जीवन प्रमाण पत्र?

सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार 60 से 80 वर्ष की आयु के पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। वहीं 80 साल से ज्यादा आयु वाले पेंशनर्स के पास लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय 1 अक्तूबर से 30 नवंबर है। अगर इस समयसीमा के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होता है तो पेंशन रुक सकती है।

घर बैठे कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

वित्त मंत्रालय के पेंशनभोगी कल्याण विभाग में जाकर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स घर बैठे भी 'AadhaarFaceRD' और 'Jeevan Praman Face App' से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

ऐप से कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

- सबसे पहले स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करें।
- अब ऐप ओपन करके अपना मोबाइल नंबर डालें।
- इसके बाद अपना चेहरा स्कैन करें।
- अब सभी जरूरी जानकारी भरें और फिर फोम के फ्रंट कैमरा से फोटो लेकर सबिमट करें।
- फोटो अपलोड होने के बाद फार्म सबमिट कर दें।

ऐसे भी करें लाइफ सर्टिफिकेट जमा

- अपने नजदीक बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
- डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए उमंग ऐप (Umang App) का इस्तेमाल करें।
- आप पोस्टमैन सर्विस के माध्यम से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

यति नरसिंहानंद ने इस्लामिक विद्वानों को इस्लाम पर शास्त्रार्थ की चुनौती दी; 100 धर्मगुरु उनके समर्थन में

गाजियाबाद: शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हजरत ख्वाजा गरीबनवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के सचिव मोहम्मद यूसुफ और उसके एक और साथी के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में सौ सनातनी धर्म गुरु अपना शपथपत्र दाखिल करेंगे। यह बात आज शिवशक्ति धाम डासना में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से साधु संतों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रखी। प्रेस वार्ता में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के साथ महेश आहूजा, डॉ. उदिता त्यागी, अनिल यादव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि वो शिवशक्ति धाम डासना में सम्पूर्ण विश्व के इस्लामिक विद्वानों को विनम्रता के साथ इस्लाम पर शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ किया गया व्यवहार आज सारी दुनिया को पता चलना ही चाहिए। आज सम्पूर्ण विश्व को पता चलना ही चाहिए कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी मस्जिदें दूसरे समुदायों के पूजा उपासना स्थल को तोड़कर बनाई गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो कल ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके विरुद्ध दायर हुई जनहित याचिका पर अपना शपथपत्र भेजेंगे।

प्रेस वार्ता में बालाजी मंदिर हिंडन विहार के श्रीमहंत मच्छेंद्र पूरी महाराज ने कहा कि यति नरसिंहानंद गिरी महाराज का पक्ष जानने की आवश्यकता है। यदि उनकी बातें सच हैं तो यह बहुत ही भयानक हैं। अगर उनकी बात सच नहीं है तो उन्हें इसका दंड मिलना चाहिए। इसीलिए संत समाज उच्च न्यायालय में हजरत ख्वाजा गरीबनवाज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से डाली गई जनहित याचिका का समर्थन करता है। हम भी सौ संत अपनी ओर से शपथपत्र देकर उच्च न्यायालय से दूध का दूध और पानी का पानी करने का अनुरोध करेंगे। प्रेस वार्ता में श्रीमहंत राघवेंद्र पुरी ने कहा कि आज सम्पूर्ण विश्व के लिए इस्लाम की सच्चाई जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को हमारा सहयोग करना चाहिए। संत समाज की ओर से श्रीमहंत राघवेंद्र पुरी, श्रीमहंत मच्छेंद्र पुरी, महंत कमल गिरी, साध्वी आस्था मां तथा अन्य संत उपस्थित रहे।

अमेरिकी चुनाव के साथ ये फैक्टर्स करेंगे बाजार की चाल को तय, निवेशकों को इन चीजों पर करना होगा फोकस

इस हफ्ते शेयर बाजार की चाल के लिए कई फैक्टर्स अहम रहेंगे। इन फैक्टर्स में सबसे जरूरी 5 नवंबर को अमेरिका में होने वाला चुनाव है। विश्वभर की नजर इस चुनाव पर बनी हुई है। इसके अलावा कंपनियों द्वारा जारी तिमाही नतीजे और एफपीआई आउटफ्लो भी बाजार के लिए मुख्य फैक्टर्स रहेंगे। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहा। अब निवेशकों का नजर आगामी हफ्ते के कारोबारी सत्र पर बना हुआ है। इस हफ्ते शेयर बाजार की चाल को कई फैक्टर्स निर्धारित करेंगे।

ये फैक्टर्स रहेंगे अहम

5 नवंबर 2024 को अमेरिका में प्रेसीडेंट पद में चुनाव होगा। इस हफ्ते शेयर बाजार की चाल को यह भी प्रभावित करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते फेड रिजर्व का ब्याज दर को लेकर फैसला आएगा। इस फैसले का असर ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा। इन सबके अलावा कंपनियों द्वारा जारी तिमाही नतीजे भी स्टॉक मार्केट के मुख्य फैक्टर्स हैं।

मार्केट एनलिस्ट के अनुसार यह सभी फैक्टर्स बाजार की चाल को प्रभावित करेगा। इन फैक्टर्स के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि मैक्रोइकोनॉमिक डेटा और ग्लोबल ट्रेंड्स बाजार की चाल को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके आगे मीना ने कहा कि कंपनियों द्वारा जारी दूसरी तिमाही के नतीजे भी बाजार की चाल को प्रभावित करेगा। इसके अलावा निवेशकों का फोकस विदेशी निवेशकों के आउटफ्लो पर बनी हुई है।

ये कंपनी जारी करेगी तिमाही नतीजे

इस हफ्ते डॉ रेड्डी, टाइटन, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगा। इसके अलावा पीएमआई मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस डेटा भी बाजार का मुख्य फैक्टर है।

ग्लोबल मार्केट पर यूएस अमेरिका का असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूएस फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती, महंगाई और जीडीपी ग्रोथ से संबंधित फैसले भी बाजार की चाल को प्रभावित करेगा।

मुहूर्त ट्रेडिंग

1 नवंबर को दीवाली के मौके पर शेयर बाजार में एक घंटे की स्पेशल ट्रेडिंग हुई। इस ट्रेडिंग को मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। इस साल नए संवत 2081 के उपलक्ष्य में यह ट्रेडिंग हुई थी। इस दिन बाजार तेजी के साथ खुला और अंत में बढ़त के साथ बंद हुआ।

'भारत में साइबर घोटाले का बहुत बड़ा नेटवर्क', ED ने डिजिटल अरेस्ट मामले में दाखिल की चार्जशीट; कई चौंकाने वाले खुलासे

ईडी ने डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें जांच एजेंसी ने आठ लोगों को आरोपी बनाया है। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान भारत में साइबर घोटालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाया गया। इसके अलावा और भी कई अहम खुलासे एजेंसी ने साइबर फ्रॉड को लेकर किए हैं। पढ़ें ईडी ने क्या-क्या कहा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'डिजिटल अरेस्ट' के खतरे से बचने का आग्रह किए जाने के बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत ही ईडी ने कर्नाटक के एक मामले में आठ लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें धोखाधड़ी की रकम लगभग 159 करोड़ रुपये है।

मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपित इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने एक बयान में बताया कि उसने पिछले माह बेंगलुरु की पीएमएलए अदालत में आठ आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने कहा, 'जांच में पाया गया कि भारत में साइबर घोटालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें फर्जी शेयर बाजार निवेश और डिजिटल अरेस्ट शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्मों के जरिये अंजाम दिया जाता है।'

ज्यादा मुनाफे का दिया जाता है लालच

पिग बूचरिंग घोटाले के नाम से प्रचलित शेयर बाजार निवेश घोटाले में लोगों को उच्च मुनाफे का लालच देकर फर्जी वेबसाइटों व भ्रामक वाट्सएप ग्रुप्स का उपयोग करके लुभाया जाता है। इन भ्रामक वाट्सएप ग्रुप्स को देखने से ऐसा लगता है कि ये प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनियों से जुड़े हैं।

ईडी ने कहा कि इस घोटाले के कुछ पीड़ितों को आरोपितों ने खुद को सीमा शुल्क और सीबीआई का अधिकारी बताकर 'डिजिटल अरेस्ट' किया, फिर उन्हें मुखौटा कंपनियों में भारी मात्रा में पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। ईडी ने कहा कि आरोपितों ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए सैकड़ों सिम कार्ड प्राप्त किए जो या तो मुखौटा कंपनियों के बैंक खातों से जुड़े थे या वाट्सएप अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इन बेनाम सिम कार्डों की वजह से घोटालेबाज पीड़ितों को धोखा दे पाते हैं और उनके तुरंत पकड़े जाने का जोखिम कम हो जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी में बदली रकम

ईडी ने बताया कि आरोपितों ने साइबर अपराधों से प्राप्त रकम को हासिल करने और उसे वैध बनाने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में 24 मुखौटा कंपनियां बनाई थीं। ये मुखौटा कंपनियां मुख्य रूप से कोवर्किंग स्पेस (जहां कोई वास्तविक कारोबार नहीं होता) पर पंजीकृत हैं। कारोबार शुरू करने के सुबूत के रूप में इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष फर्जी बैंक स्टेटमेंट दाखिल किए थे। ईडी की जांच में पाया गया कि आरोपितों ने प्राप्त रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदला और विदेश में ट्रांसफर कर दिया। ईडी ने इस मामले में 10 अक्टूबर को आरोपपत्र दाखिल किया था और अदालत ने 29 अक्टूबर को इस पर संज्ञान लिया था।

ट्रक मालिक संघ की चेतावनी 10 तारीख से परिवहन बंद कर दिया जायेगा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: ट्रक मालिक संघ की चेतावनी 11वीं सूत्री मांगें पूरी नहीं होने पर 10 तारीख से परिवहन बंद कर दिया जायेगा। यह निर्णय 10 जिलों के 15 ट्रक मालिक संघों की संयुक्त बैठक में लिया गया। ट्रक मालिकों के लिए अपना दावा पूरा करने की 9 तारीख है। अन्यथा, 5,000 से अधिक ट्रक अनिश्चित काल तक विरोध प्रदर्शन करेंगे।नदी की रेत के परिवहन के दौरान अनुचित जुर्माने

भुबनेश्वर में सुबह भूकंप आया

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

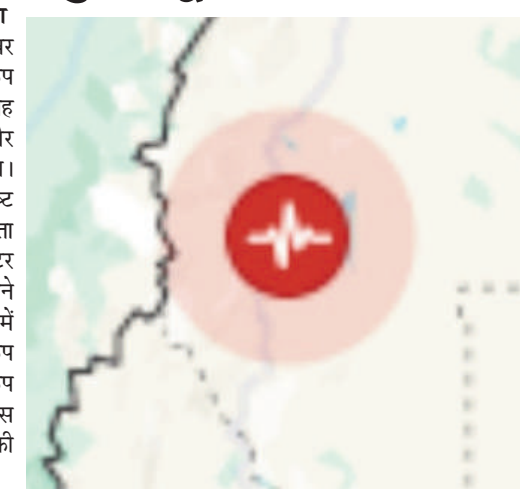

भुबनेश्वर: ओड़िशा की राजधानी भुवनेश्वर सुबह से सुबह तक कांप उठी। आज सुबह भूकंप आने की खबरें आ रही हैं। भूकंप की सूचना सुबह 7:15 बजे दी गई। भीमटागी, सीआरपी और नयापली के निवासियों ने भूकंप महसूस किया। लेकिन मौसम विभाग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण नेशनल जियोलॉजिकल सेंटर की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आने की बात कही जा रही है। जबकि भुवनेश्वर में भूकंप दुर्लभ हैं, कुछ लोगों ने आज हल्के भूकंप का अनुभव किया है। हालांकि, यह हल्का भूकंप था, इसलिए किसी नुकसान की खबर नहीं है। इस भूकंप के 2 से 3 साल बाद लोगों में एक तरह की दरार पड़ गई है।

सीरवी समाज प्रीमियर लीग-7 क्रिकेट प्रतियोगिता व महिला वर्ग के खेल 10 से

परिवहन विशेष न्यूज

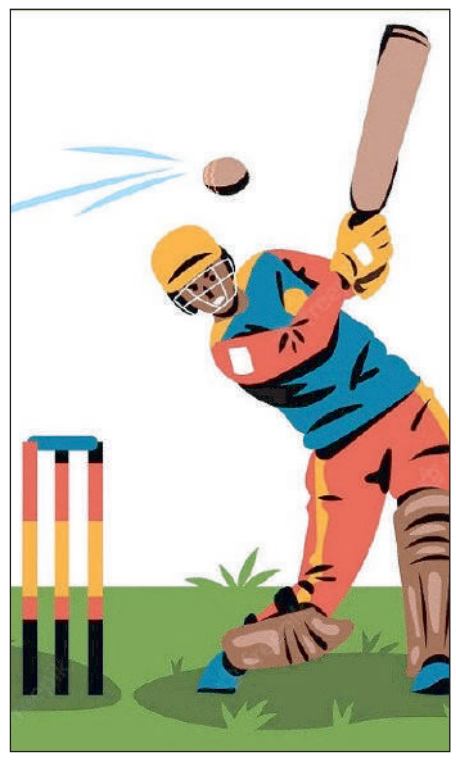

हैदराबाद सीरवी फ्रेन्डस् क्लब हैदराबाद द्वारा आयोजित सीरवी समाज प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के 7 वें संस्करण तथा महिला वर्ग के खेलों का शुभारम्भ रविवार 10 नवम्बर को सीरवी समाज क्रिकेट ग्राउंड अलियाबाद एवं श्रेष्ठा क्रिकेट ग्राउंड अलियाबाद में आयोजित किया जाएगा। फ्रेन्डस् क्लब के सुरेश सैंणचा ने बताया कि हर वर्ष की भांति सीरवी समाज प्रीमियर लीग-7 का तथा इस प्रतियोगिता के साथ महिला वर्ग के खेलो का भव्य आयोजन 10 नवंबर को प्रातः 7.15 को मुख्य प्रायोजक वंडर वॉल पुट्टी की टीम तथा मुख्य अतिथियों के करकमलों द्वारा किया जायेगा। इस बार खेलों को लेकर महिला वर्ग खिलाड़ीयों में भारी उत्साह नजर आ रहा है।

क्रिकेट प्रतियोगिता मे कुल 18 टीमें भाग लेंगी। जिसमें आईजी बिरमगुड़ा ,करमनघाट, एल बी नगर, नागोल वेरिस ,संगारेड्डी, शमशाबाद , मेडचल जिडिमिटला, कापरा किंग्स, रामनगर, ऑल विन 11, बालनगर सिकंदराबाद, आईजी फैरडकलब, आईजी गुट्टा 11, हायतनगर, कुकटपल्ली, सैनिकपुरी, टी एम जी टाइटन्स होंगी । इस बार प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम 5 लीग मैच खेलेगी। तथा 4 क्वाटर फाईनल, 2 सेमीफाइनल और फाईनल मुकाबले खेले जाएंगे। क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ साथ महिला वर्ग के खेलों में एथेलेटिक्स तथा पारंपरिक खेल शामिल होंगे। महिला वर्ग के सभी खेल सिरवी क्रिकेट ग्राउंड अलियाबाद शामिरपेट में आयोजित होंगे। यह प्रतियोगिता सिरवी फ्रेंड्स क्लब हैदराबाद तेलंगाना द्वारा आयोजित की जा रही है।और फाईनल मुकाबला खेला जाएगा। भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की जाएगी। कार्यक्रम का लाईव टेलीकास्ट युट्युब चैनल पर किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सीरवी फ्रेन्डस् क्लब के सभी सदस्यों का विशेष सहयोग रहेगा। सभी सीरवी बन्धुओं से निवेदन है इस प्रतियोगिता मे अपना तन-मन-धन से सहयोग करके प्रतियोगिता को सफल बनावे।

दिमागी शांति वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी दौलत : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

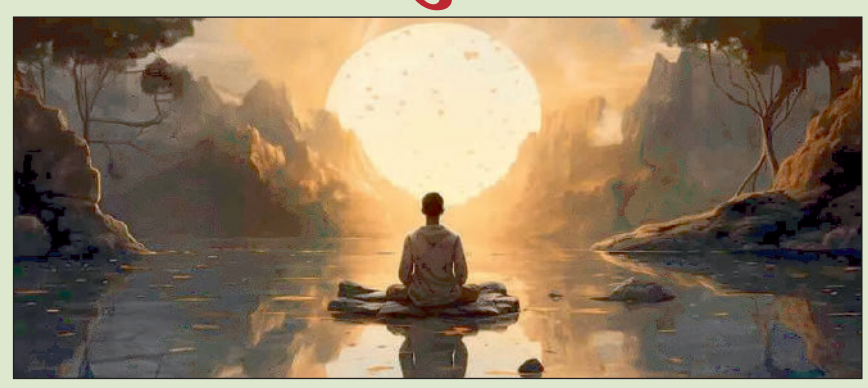

दिमागी शांति के बिना सभी भौतिक सुखों का कोई मूल्य नहीं : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान
जब हम अपने अंदर संतोष और संतुलन पाते हैं, तभी असली खुशी का अनुभव करते हैं : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

आगरा, संजय साग़र सिंह। दिमागी शांति वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जब हम अपने अंदर संतोष और संतुलन पाते हैं, तभी असली खुशी का अनुभव करते हैं। भौतिक संपत्ति निश्चित रूप से सुख का अनुभव करवा सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। मानसिक शांति का अनुभव केवल आंतरिक संतुलन से संभव है।

इस सन्दर्भ में वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हुए कहा,- दिमागी शांति दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हम दिन की शुरुआत करते हैं, तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को पर लौटते हैं, तब लगता है शांति ही जीवन है। हर परिस्थिति में शांत बने रहना जीवन की मजबूती है, वहीं, सारी सुख सुविधा हो, लेकिन शाति न हो तो समझना चाहिए कि सुविधा को गलती से सुख समझा जा रहा है।जीवन में जब हम अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को समझते हैं, तो वही हमें असली सुख और संतोष की ओर ले जाता है।

उन्होंने कहा,- हम सभी जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं। अतीत की यादें, वर्तमान की चुनौतियां, और भविष्य की चिंताएं हमें चिंतित कर सकती हैं। लेकिन, जो लोग अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, वे ही जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार कर पाते हैं। मन की शांति केवल बाहरी परिस्थितियों को ठीक करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर क्या चल रहा है, यह समझने में भी है। सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं, तब हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रह सकते हैं और उनके फल भी सकारात्मक होते हैं।

श्री खान ने आगे कहा,- शांति की चाहत रखने वालों को अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। इसलिए, अपने मन को शांत रखना और उसे सही दिशा में लगाना आवश्यक है। अंत में, दिमागी शांति के बिना सभी भौतिक सुखों का कोई मूल्य नहीं। जीवन में असली खुशी और संतोष तभी मिलते हैं जब हम आंतरिक शांति को प्राथमिकता देते हैं।

भारतीय राजनीति में नारों की गूंज-बटेंगे तो कटेंगे बनाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे+जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे=एक है तो सेफ़ है

क्या नेता वोटरों को नारों में उलझा पाएंगे? समझदार वोटर किसक़े साथ जाएंगे? भारत के महाराष्ट्र झारखंड राज्यों व अन्य उपचुनावों में दिए नारों से राजनीति गरमाई-वोटरों ने नारों पर मंथन करने की मानसिकता बनाई

वैश्विक स्तरपर लोकतंत्र के सबसे बड़े और सबसे पुराने देश भारत और अमेरिका में 5 नवंबर 2024 व भारत के महाराष्ट्र झारखंड मैं पूर्ण 5 वर्षीय चुनाव व कुछ राज्यों के उप चुनावों पर दुनियाँ की नज़रें लगी हुई है इसलिए कि दुनियाँ जानती है कि अमेरिका का विश्व पर दबदबा है, इसकी हरी झंडी मिलने से ही विश्व में कोई काम होते हैं, तो वही महाराष्ट्र मुंबई को भारत की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो झारखंड को आदिवासी गढ़, इन जनजातियों का सबसे बड़ा सुबह तो यूपी को पीएम की कुर्सी तक जाने का रास्ता माना जाता है, इसलिए विश्व की टकटकी नज़रें इसके परिणाम जानने के लिए उत्सुक है। परंतु इन चुनावी माहौल में देश व राज्यों में माहौल अति तेज गरमाया हुआ है।एक औरजहां अमेरिकी राष्ट्रपति की वूमेन विरोधी छवि तो वही हैरिस की ब्लैकिश छवी है, परंतु टक्कर जोरदार होनी है,तो वहीं भारत में इस माहौल में नारों का नगाड़ा धूम धड़ाक्के से बज रहा है। सबसे पहले यूपी सीएम ने बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, हरियाणा फतेह हुआ वहीं इस नारे को आरएसएस व पीएम का भी सपोर्ट आधार मिला जिससे यूपी के पूर्व सीएम युवा नेता हड़बड़ा गए, व नारा दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे फिर पूर्व सीएम मायावती क्यों पीछे रहेगी उन्होंने भी नारा दिया जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, फ़रि अब पीएम ने भी एक सभा में नारा दिया एक है तो सेफ़ हैं इन सब नारों की चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे। अब सवाल है क्या नेता वोटरों को नारों में उलझा पाएगी? समझदार वाटर किसके साथ जाएंगे, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारतीय राजनीति में नारों की गूंज, बटेंगे तो कटेंगे बनाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे प्लस जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे इक्वल टू एक है तो सेफ़ है।

साथियों बात अगर हम यूपी सीएम द्वारा दिए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे की करें तो, यूपी में उपचुनाव के बीच पोस्टर के स्लोगन की सियासत शुरू हो गई है।यूपी सीएम के नारे बंटेंगे तो कटेंगे पर संघ परिवार की मुहर के बाद इसके अब होर्डिंग दिखने लगे हैं। पोस्टर के जरिए पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिल रही है। वहीं इस नारे को लेकर विपक्ष नेयूपी सीएम को घेरना भी शुरी कर दिया है।एसपी के अध्यक्ष ने सीएम के नारे पर टिप्पणी करते हुए राजनीतिक इतिहास का सबसे ख़राब नारा बताया है।सीएम ने आगरा में एक कार्यक्रम में कहा था कि आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वे गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। इसके बाद यह स्लोगन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।यूपी के साथ ही देश की राजनीति में भी इन दिनों एक नारे को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। यह नारा बटेंगे तो कटेंगे का है। यह नारायूपी सीएम ने दिया है। अब सपा ने उनके इस नारे पर जोरदार पलटवार किया है। बता दें यूपी में नौ विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव की वजह से चुनावी माहौल काफी गर्म है। इस उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर है।बुलडोजर एक्शन के बाद अब सीएम का एक स्लोगन भी चल पड़ा है।जैसे 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हर जगह बुलडोजर छाया रहा, अभी सीएम का दिया एक नारा सबसे ज्यादा चर्चित है, बंटेंगे तो कटेंगे- और चुनावी माहौल में सीएम की बात को संघ से लेकर पीएम तक एनडोर्स कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सीएम के नारे बटेंगे तो कटेंगे के प्रभाव की भी परख होगी। वजह ये है कि उपचुनाव को खुद फ्रंट से लीड कर रहे यूपी के सीएम के इस नारे को विपक्ष की जातीय गोलबंदी के काट के तौर पर देखा जा रहा है। इस नारे ने हाल ही में हरियाणा चुनाव में रंग दिखाया है और महाराष्ट्र, झारखंड में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। ऐसे में ये तय है कि यूपी उप चुनाव की रैलियों और जनसभाओं में ये नारा गूंजेगा। वहीं अब इस नारे को संघ का समर्थन मिलने के बाद 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सियासी रणनीति इसके इर्द-गिर्द होने के संकेत भी मिल रहे हैं।

साथियों बात गअगर हम यूपी युवा नेता द्वारा दिए गए नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे कि करें तो, यह नारा देकर कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दे दिया है।वहकार्यकर्ताओं से एक साथ आने और आपस में जुड़ने की बात करते दिख रहे हैं। दरअसल, पिछले दिनों कई स्थानों पर पार्टी कैडर में बिखराव की आशंका जताई जा रही है। वहीं, यूपी की राजनीति में यादव वोट बैंक में बिखराव की भी आशंका गहराई है। इसलिए, युवा नेता जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा देते दिख रहे हैं।युवा नेता ने कहा नारे हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। नकारात्मक नारा हमेशा कमजोर लोग ही देते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो कहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नारे को आगे बढ़ते हुए वह कहते हैं कि पीडीए जुड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। युवा नेता यूपी के सीएम पर हमलावर रुख अपनाते हुए दिखते हैं। यूपी क़े सीएम के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर काफी चर्चा हो रही है। इसके पलटवार में समाजवादी पार्टी ने भी एक पोस्टर जारी किया है, जिसपर लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अब यूपी की एक और प्रमुख पार्टी बसपा भी इस बयानबाजी में शामिल हो गई है। बसपा चीफ ने कहा कि बसपा का नारा, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे, है। उन्होंने कहा कि जब से बसपा ने उपचुनाव में उतरने का ऐलान किया है, सपा और बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे।

साथियों बात अगर हम पूर्व सीएम मायावती के नारे जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे की करें तो, बसपा चीफ़ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान जारी करते हुए लिखा, यूपी में नौ विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी के दमदारी से उतरने से भाजपा और सपा की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए विकास से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे और सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारे दिए हैं। उनकी दोगली नीतियों से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप हमेशा तक बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे।

साथियों बात अगर हम माननीय पीएम के मास्टर स्ट्रोक एक है तो सेफ़ हैं नारे की करें तो, पीएम ने राष्ट्रीय एकता और यूसीसी की जोरदार वकालत की। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों को अर्बन नक्सलियों के नए मॉडल से सावधान रहने की जरूरत है, जिनका एकमात्र एजेंडा अराजकता फैलाना और देश को अस्थिर करना है। उन्होंने कहा कि आंतरिक और बाहरी ताकतें देश की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को देखते हुए भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही हैं।महराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब एक हैं तो सेफ हैं का नया बयान सामने आया है।पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए एक नया नारा एक हैं तो सेफ हैं दिया।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारतीय राजनीति में नारों की गूंज-बटेंगे तो कटेंगे बनाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे + जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे=एक है तो सेफ़ है।क्या नेता वोटरों को नारों में उलझा पाएंगे? समझदार वोटर किसक़े साथ जाएंगे?भारत के महाराष्ट्र झारखंड राज्यों व अन्य उप चुनावों में दिए नारों से राजनीति गरमाई-वोटरों ने नारों पर मंथन करने की मानसिकता बनाई।

-संकलनकर्ता लेखक- क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023